04 - भारत में कम्युनिस्ट आंदोलनः उत्थान और पतन की अकथ-कथा

05 - डिका जनजातिः गायों में निहित हैं उनके सुख-दुख

A Daily News Magazine

भोपाल

बुधवार, 13 मई, 2026

06 - सांसद सावित्री ठाकुर के प्रयासों से धार -महू लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा...

07 - शिक्षा संबल योजना के तहत निःशुल्क नीट कोचिंग प्रवेश...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 250, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

पाक, चीन के खिलाफ भावी युद्ध के लिए भारत क्या तैयारी करे

ले.जन. एच.एस. पनाग (रि.)

ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल की जंग ने आधुनिक युद्ध से जुड़े एक अहम सवाल को साफ कर दिया है। ज्यादा ताकतवर देश जब हवाई हमले शुरू करता है, तो शुरुआत में उसका दबदबा बन जाता है, लेकिन इससे साफ और पूरी जीत नहीं मिलती। ताकतवर पक्ष चाहता है कि पहल उसी के हाथ में रहे। इन हमलों के पीछे 'फोर्स मल्टीप्लायर' की ताकत भी होती है, ताकि मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर दुश्मन को हराया जा सके।

कमजोर दुश्मन अगर जवाबी हमला कर सकता है, तो वह शुरुआती हमलों को सह लेता है और युद्ध को लंबा खींचने के लिए विषम रणनीति अपनाता है, जिससे वह दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यह तरीका परमाणु ताकत वाले देशों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि वे युद्ध को परमाणु स्तर से नीचे रखना चाहते हैं। ऐसे युद्ध में जमीन, अर्थव्यवस्था और सेना– हर स्तर पर भारी नुकसान हो सकता है।

भारत के लिए यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। भविष्य में चीन छोटा, हाई-टेक और जल्दी खत्म होने वाला युद्ध लड़ना चाहेगा। पाकिस्तान इसे लंबा और असमान (विषम) युद्ध बनाना चाहेगा। दोनों देश परमाणु ताकत के असर में कदम उठाएंगे, जिससे युद्ध बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जोखिम लेने की कोशिश जारी रहेगी। भारत-पाकिस्तान युद्ध में चीन का सहयोग खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही (ISR) तक सीमित रह सकता है, जिसमें अंतरिक्ष और साइबर युद्ध भी शामिल होंगे, लेकिन भारत-चीन युद्ध में पाकिस्तान जरूर दूसरा मोर्चा खोल देगा।

भारत से बराबरी की सीधी लड़ाई लड़ने में पाकिस्तान की कोई रुचि नहीं होगी। उसने अपनी सोच 'ऑपरेशन सिंदूर' में दिखा दी है। लड़ाई के पहले घंटे में जवाबी हवाई हमले करके उसने भारतीय वायुसेना को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बाद अगले 87 घंटे तक वह अपने सुरक्षित ठिकानों में छिपा रहा। फिर 72 घंटे तक उसने ड्रोन के झुंड से करीब 600 हमले किए। इन हमलों में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम वाले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।

इसी दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर जोर दिया। 9 मई 2026 की रात पूरे पाकिस्तान पर बड़े हवाई हमले किए गए। पाकिस्तान की रणनीति सही थी, लेकिन उसे लागू करने में गलती हो गई। इसके अलावा उसके पास मजबूत मिसाइल और अच्छे ड्रोन नहीं थे। मेरा अनुभव कहता है कि पाकिस्तान अगली बार यही रणनीति फिर अपनाएगा। वह अपने लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करेगा, बेहतर मिसाइल और ड्रोन लाएगा, अपने रक्षा ढांचे को और मजबूत बनाएगा और अंडरग्राउंड युद्ध को ज्यादा अपनाएगा। उसकी विषम रणनीति भारत के अंदरूनी इलाकों और समुद्री ऑपरेशनों में, लक्ष्य चुनने और भाड़े के सैनिकों/एजेंटों के इस्तेमाल से दिखेगी।

पाकिस्तान विमान, मिसाइल और ड्रोन से न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा, बल्कि बड़े शहरों को भी निशाना बनाएगा ताकि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक असर पड़े। वह अपने नैतिक पक्ष को ऊंचा दिखाकर भारत के नैतिक पक्ष को चुनौती देने की कोशिश करेगा और नीति बनाने वालों को उलझन में डालेगा। पाकिस्तान रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बिगाड़ने के लिए पावर ग्रिड, तेल रिफाइनरी, पेट्रोल डिपो, ट्रांसपोर्ट हब और कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे ज़रूरी ढांचे को भी निशाना बना सकता है।

चीन के साथ मिलकर वह बैंक, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और शेयर बाजार जैसे आर्थिक और वित्तीय सिस्टम पर साइबर हमले कर सकता है। इनका मकसद कुछ समय के लिए सिस्टम को ठप करना होगा, जिसका बड़ा असर पड़ सकता है।

समुद्र भी विषम युद्ध का दूसरा क्षेत्र बन सकता है। नौसेनाएं समुद्र पर नियंत्रण के लिए लड़ेंगी, लेकिन विषम रणनीति के तहत ड्रोन और मिसाइल से व्यापारिक जहाजों और टैंकरों पर हमले हो सकते हैं। बंदरगाहों को बारूदी सुरंगों से निशाना बनाया जा सकता है. 'मोस्क्वीटो नेवी' 500-600 किमी तक के समुद्री क्षेत्र को जहाजों के लिए खतरनाक बना सकती है।

अनुभव बताते हैं कि बड़ी ताकतें जल्दी जीत चाहती हैं। मेरा मानना है कि अनिश्चितता के कारण चीन के साथ सीमित युद्ध की संभावना कम है, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत और सीमा विवाद के कारण चीन दबाव बनाने के लिए ताकत दिखा सकता है।अमेरिका की तरह वह भी कम समय और सीमित क्षेत्र में लड़ाई करके जल्दी जीतने की कोशिश करेगा, बिना पहाड़ों में लंबी पारंपरिक लड़ाई के। भारत का लक्ष्य होना चाहिए कि वह चीन के तकनीकी हमलों का जवाब दे और उसकी विषम रणनीति को नाकाम करके उसे रणनीतिक रूप से हराए। पूर्वी लद्दाख संकट के दौरान भारत ने चीन की भारी तैनाती और लगभग 1000 वर्ग किमी क्षेत्र पर कब्ज़े की कोशिश का शांत तरीके से जवाब दिया। इससे गतिरोध तो बना, लेकिन भारत अपनी कमजोर स्थिति के कारण बातचीत में पुरानी स्थिति वापस नहीं ला सका।

भूगोल के कारण चीन को पहले कदम उठाने का फायदा मिलता है, इसलिए भारत को सिर्फ शांत रहने की बजाय मजबूत कदम उठाने होंगे। ताकतवर दुश्मन के हवाई हमलों का सबसे अच्छा जवाब अंडरग्राउंड युद्ध है। इसे पूरी तरह लागू करना चाहिए। साथ ही मजबूत एअर डिफेंस भी बनाना चाहिए।

हवाई और ज़मीनी जवाबी कार्रवाई सीमा के दूसरे हिस्सों में भी करनी चाहिए, जहां हमें भौगोलिक बढ़त मिल सकती है। मलक्का जलडमरूमध्य चीन की अर्थव्यवस्था की बड़ी लाइफलाइन है। अंडमान-निकोबार द्वीप इसके पास हैं, इसलिए भारत यहां दबाव बना सकता है। अरब सागर में भी ग्वाडर, पासनी और कराची बंदरगाहों तक पहुंच रोककर चीन की अर्थव्यवस्था पर असर डाला जा सकता है। 'मोस्क्वीटो फ्लीट' बनाना भी फायदेमंद हो सकता है। तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक नेता दलाई लामा और उनकी सरकार भारत में है। जानकारी के मुताबिक 10-12 हजार तिब्बती सैनिक स्पेशल फोर्स के रूप में प्रशिक्षित हैं और भारत के साथ लड़ते रहे हैं। तिब्बत चीन की कमजोरी है। अगर चीन हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करता, तो हमें भी तिब्बत में रणनीतिक कदम उठाने से नहीं हिचकना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य सावधानी से चुनने चाहिए और मुख्य रूप से चीनी सेना 'PLA' पर ध्यान देना चाहिए।

विषम रणनीति में दुश्मन की कमजोरियों को निशाना बनाया जाता है या उसकी कम तैयारी का फायदा उठाया जाता है। हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से युद्ध का तरीका अपनाता है। विषम रणनीति का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इसमें नुकसान होता है क्योंकि यह अक्सर प्रतिक्रिया में किया जाता है। असली चुनौती यह है कि ऐसी रणनीति को पहले से समझकर उसे कैसे रोका जाए और जरूरत पड़ने पर उसका फायदा कैसे उठाया जाए।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

पेपर लीक का आरोप, 'नीट' एग्जाम रद्द

● 23 लाख स्टूडेंट बैठे थे ,अब सीबीआई करेगी जांच

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द कर दी है। यह फैसला पेपर लीक होने के आरोप के चलते लिया गया। सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दिया गया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। परीक्षा में 22.79 लाख छात्र शामिल हुए थे। एनटीए ने कहा है कि प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। उनके एग्जाम सेंटर्स में भी बदलाव नहीं होगा। रीएग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी। दिल्ली में जब शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से नीट परीक्षा रद्द और पेपर लीक होने पर पत्रकारों ने सवाल किया तो वह बिना जवाब दिए निकल गए। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली ने एएपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नीट एग्जाम 2013 में शुरू हुआ था। एनटीए ने इसे पहली बार 2019 में कराया। 2024 में पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर परीक्षा रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एग्जाम कैंसिल करने से इनकार किया था।

● **720 में से 600 नंबर के सवाल कॉमन**– जांच में सामने आया है कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल दो दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। ये गेस पेपर केरल के एक कॉलेज से नीट कर रहे स्टूडेंट ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को भेज दिया था। स्टूडेंट्स तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं।

नासिक से पेपर लीक की खबर

सूत्रों से खबर है कि लीक हुए पेपर की सबसे पहली कॉपी नासिक पहुंची थी। वहीं से हरियाणा गई। हरियाणा से पेपर के 10 सेट तैयार किए गए और फिर उन्हें बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे अलग-अलग राज्यों में भेजा गया। एनटीए ने बताया कि 8 मई 2026 को ही इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हिमंता दूसरी बार बने असम के मुख्यमंत्री

2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों के एमएलए बने मंत्री

गुवाहाटी (एजेंसी)। हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में उन्हें पद और गोपनियता की शपथ दिलाई। हिमंता के अलावा 4 विधायकों भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नेओम, एजीपी के अतुल बोरा, बीपीएफ के चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें दो बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से हैं। शपथ कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा

मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी-एनडीए शासित राज्यों के सीएम और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। हिमंता का पूरा परिवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुवेंदु अधिकारी, देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, पवित्र मार्घेरिटा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है।

सीएम यादव ने मंत्रियों को दिए निर्देश

पीएम मोदी की अपील-1 साल तक न खरीदें सोना, विदेश यात्राओं पर भी लगाम

भोपाल (नप्र)। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए नागरिकों से कुछ कड़े और जरूरी त्याग करने की अपील की है। पीएम की इस मुहिम को जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रियों को खास निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को इस संकट के प्रति जागरूक करें और राष्ट्रीय हित में पीएम के संदेश को फैलाएं।

विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की बड़ी कवायद– कैबिनेट बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने मीडिया को जानकारी दी कि देश हर साल आभूषणों के लिए 6 लाख करोड़ रुपये से

अधिक का सोना आयात करता है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि जब तक शादी-ब्याह न हो, तब तक कम से कम एक साल के लिए सोना खरीदने से बचें। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद मिलेगी, जो मौजूदा वैश्विक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहद जरूरी है।

ई-रिक्शा से अध्यक्ष, साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे जस्टिस

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री के पेट्रोल-डीजल के कम उपयोग करने की अपील के बाद भोपाल में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के लिए ई-रिक्शा से, जबकि जबलपुर में जस्टिस साइकिल चलाकर हाई कोर्ट पहुंचे। हालांकि, सत्येंद्र भूषण सिंह भोपाल के अवधपुरी स्थित अपने निजी आवास से जब भाजपा कार्यालय के लिए निकले तो उनके समर्थक कार और बाइक से साथ चल रहे थे। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन ने भी पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि वे खुद केवल तीन लोगों के साथ ई-रिक्शा से भाजपा

कार्यालय पहुंचे। बाकी कितने लोग गाड़ियों से आए, उन्हें जानकारी नहीं है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी ई-स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे।

कई बोर्ड-निगमों में पदभार ग्रहण– मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पंकज जोशी, मध्य प्रदेश कुश समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रभु दयाल कुशवाहा ने भी अपना कार्यभार संभाला।

जबलपुर में हाईकोर्ट जस्टिस साइकिल से पहुंचे कोर्ट– वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल भी करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर हाई कोर्ट पहुंचे।

यूएई, इटली समेत 5 देशों की यात्रा करेंगे मोदी

● ईरान-अमेरिका में तनाव के बीच बेहद अहम है दौरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच दुनियाभर में पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक यूरोप और यूएई की यात्रा पर जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा के दौरन वह ऊर्जा सहयोग और व्यापार को बढ़ाने को लेकर कई समझौते कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई और इटली में रुकेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का भी दौरा करेंगे। वह 15 मई को सबसे पहले यूएई पहुचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के

दौरान ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूरोप के देशों के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक यात्रा के दौरान सभी देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी।

बता दें कि यूएई भारत का बड़ा एनर्जी पार्टनर है। इसके अलावा भी निवेश के मामले में वह भारत का सातवां सबसे बड़ा स्रोत है।

यहां 45 लाख से ज्यादा भारतीय भी रहते हैं। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचेंगे और पीएम रॉब जेटेन से मुलकात करेंगे। वह 17 मई तक नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनर्स के न्योते पर 17 से 18 मई तक के लिए स्वीडन में रहेंगे।

नवाचार को लेकर हो सकती है अहम बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड दूसरी बार जा रहे हैं। यहां वह पीएम विलियम- अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मिलेंगे। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान रक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और नवाचार के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और यहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा रक्षा, सुरक्षा, नवाचार, हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और जल पर रणनीतिक साझेदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय बैठकों और घनिष्ठ सहयोग की गति को और मजबूत करेगी। मंत्रालय ने कहा कि उनकी यह यात्रा बहुआयामी साझेदारी को और गहरा और विस्तारित करने का अवसर प्रदान करेगी। अपनी वार्ता में दोनों पक्ष हरित परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, लोगों का लोगों से संबंध और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

शरद की सुबह

हम बेहद भाग्यशाली हैं
कि हम ठीक ठीक नहीं जानते
हम किस तरह के संसार में रह रहे हैं
आपको यह जानने के लिए
बहुत, बहुत लम्बे समय तक जीना होगा
निस्संदेह इस संसार के
जीवन से भी ज़्यादा लम्बे समय तक
चाहे तुलना करने के लिए ही सही
हमें दूसरे संसारों को जानना होगा
हमें देह से ऊपर उठना होगा
जो बस
बाधा पैदा करना
और तकलीफ़ें खड़ी करना जानती है
शोध के वास्ते
पूरी तस्वीर के वास्ते
और सुनिश्चित निष्कर्षों के वास्ते
हमें समय से परे जाना होगा
जिस के भीतर हर चीज़ हड़बड़ी में भागती और
चक्कर काटती है
उस आयाम से
शायद हमें त्याग देना होगा
घटनाओं और विवरणों को
सप्ताहों के दिनों की गिनती
तब अपरिहार्य रूप से
अर्थहीन लगने लगेगी
पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालना लगेगा
मूर्खतापूर्ण जवानी की सनक
'घास पर न चलें' लिखा बोर्ड लगेगा
पागलपन का लक्षण।

– विस्लावा शिम्बोर्स्का

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 13 मई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

'तारीख पर तारीख' वाला मामला अब होगा खत्म

● सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश,जमानत याचिकाओं की सुनवाई पर बड़ा कदम

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट में लंबित जमानत मामलों को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कहा है कि हाई कोर्ट में वर्षों से लंबित हजारों जमानत याचिकाएं स्वतंत्रता के अमूल्य अधिकार का उल्लंघन करती हैं। जमानत से जुड़े मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए तय सिस्टम बनाया जाना जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट को जमानत याचिकाओं पर सबसे कम समय में निर्णय लेने के लिए सराहना दी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जमानत याचिकाओं की भारी संख्या लंबित है, पीठ ने इस तथ्य की सराहना की कि वहां

लंबित मामलों की संख्या इतनी अधिक है कि न्यायाधीशों को प्रतिदिन लगभग 200 जमानत याचिकाओं की सुनवाई करनी पड़ती है। **तेजी और नियमित तरीके से हो जमानत याचिका पर सुनवाई-** चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सोमवार को सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि जमानत याचिकाओं की सुनवाई तेजी से और नियमित तरीके से हो। जमानत के मामलों को हर हफ्ते या कम से कम दो हफ्ते में एक बार जरूर लिस्ट किया जाए। इसके लिए ऑटोमेटिक लिस्टिंग सिस्टम तैयार करने को कहा गया है ताकि किसी केस की सुनवाई सिर्फ तारीख पर तारीख तक सीमित न रह जाए। वर्तमान में, अदालतों की सामान्य प्रक्रिया यह है कि वे आरोपी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हैं और संबंधित राज्य सरकार,जांच एजेंसी या अभियोजन पक्ष से जवाब मांगते हैं।

लंबे समय तक केस को सुनवाई के लिए लंबित न रखें

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो पाती, उन्हें अपने आप दोबारा लिस्ट किया जाए। किसी केस को लंबे समय तक बिना सुनवाई के लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। सभी हाईकोर्ट को मामलों के निपटारे के लिए एक तय टाइमलाइन भी बनानी होगी। कोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट में होने वाली देरी पर भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों से जुड़े मामलों में जांच अधिकारियों को ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा। अगर जांच में ढिलाई बरती गई तो इसका फायदा आरोपी को जमानत मिलने के रूप में मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट, जांच एजेंसियां और सरकारें मिलकर बढ़िया सिस्टम बनाएं।

संक्षिप्त समाचार

तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास शराब दुकानें बंद होंगी

● भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी को स्पेशल ऑफीसर बनाया

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को राज्य में मंदिरों, स्कूल-कॉलेज और बस स्टैंड के पास की कुल 717 शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया। इसके साथ ही सीएम विजय ज्योतिषी रिकी राधन पंडित को ऑफीसर इन स्पेशल ड्यूटी बनाया है। रिकी ने ही विजय के सीएम बनने की भविष्यवाणी की थी। साथ ही उनकी शपथ का समय भी बदलवाया था। सीएम

जोसेफ विजय शपथ लेने के साथ ही ऐक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार विधानसभा में पहली स्पीच दी थी। इसके बाद कई आदेश जारी किए। टीवीके सरकार को 13 मई को अपना फ्लोर टेस्ट भी देना है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को टीवीके विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति पर विश्वास प्रस्ताव समेत किसी भी वोटिंग में हिस्सा लेने पर रोक लगाई है। सेतुपति ने तिरुपत्तूर सीट से टीवीके उम्मीदवार केआर पेरियाकरुप्पन को महज एक वोट से हराया था। पेरियाकरुप्पन ने वोटों की दोबारा गिनती की मांग की थी। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी और एन सेंथिलकुमार की वेकेशन बेंच की तरफ से लगाई गई रोक के बाद सेतुपति किसी भी अविश्वास प्रस्ताव पर भी वोट नहीं दे सकते। याचिका में पेरियाकरुप्पन ने मतगणना प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया था। टीवीके विधायक सेतुपति ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। **टीवीके ने पार्टी सदस्यों के लिए भी बनाए रूल-** पार्टी के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में सदस्यों के लिए नया निर्देश जारी किया गया है।

अब फ्लाइट से सफर नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र के मंत्री

● पीएम की अपील के बाद सीएम फडणवीस का ऐक्शन

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की मंजूरी के बिना अब महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री को सरकारी विमान या चार्टर्ड विमान का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा खर्च नियंत्रण और ईंधन बचत पर जोर दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने

भी इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रियों की हवाई यात्राओं पर नियंत्रण रखने के लिए नई प्रशासनिक प्रक्रिया लागू की गई है। इसके तहत किसी भी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी को सरकारी विमान का उपयोग करना हो तो पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी मिलने के बाद ही विमान उपलब्ध कराया जाएगा। **पीएम मोदी की अपील के बाद तेज हुई कार्रवाई-** प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईंधन बचत, सरकारी खर्च में कटौती और संसाधनों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग की अपील की थी। इसके बाद विभिन्न राज्यों में सरकारी खर्चों पर नियंत्रण को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थीं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने उसी दिशा में अमल शुरू कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, कुछ मंत्री कम दूरी के लिए भी विमान का उपयोग कर रहे थे। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। अब केवल अत्यावश्यक और आधिकारिक कार्यों के लिए ही विमान उपयोग की अनुमति दी जाएगी। **खर्च नियंत्रण पर सरकार का फोकस-** राज्य की आर्थिक स्थिति, बढ़ता राजस्व दबाव और विकास कार्यों के लिए आवश्यक निधि को देखते हुए सरकार खर्च नियंत्रण की नीति पर जोर दे रही है। सरकारी बैठकों, दौरों और यात्रा खर्चों में अनुशासन लाने के निर्देश भी विभिन्न विभागों को दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।

● सुवेंदु अधिकारी का पीए मर्डर केस

सीबीआई करेगी जांच

● 7 अफसरों की एसआईटी गठित,बिहार-यूपी से गिरफ्तार 3 आरोपी 13 दिन की पुलिस कस्टडी में

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (पीए) चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेते ही 7 मेंबर्स की स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम बनाई है। टीम की अगुआई आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। इस केस में अब तक बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस नेतीनों को नॉर्थ 24 परगना के बारासात कोर्ट में पेश किया।

हत्या में 8 लोगों के शामिल होने का शक

जांच एजेंसियों का मानना है कि हत्या की साजिश और वारदात में कम से कम 8 लोग शामिल थे। आरोपियों ने वारदात से पहले कई दिनों तक रेकी की थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावरों की कार हत्या से पहले बाली टोल प्लाजा से गुजरी थी। यहां एक व्यक्ति ने यूपीआई से टोल पेमेंट किया था।

● बिहार और यूपी से पकड़े गए 3 आरोपी- पुलिस ने मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार किया है। मयंक और विक्की को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया गया। वहीं, उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले राज सिंह को अयोध्या से 10 मई को पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद राज सिंह का एक पोस्टर सामने आया है। इसमें उसने खुद को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव बताया है। उसके फेसबुक अकाउंट में मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ की तस्वीर है। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के साथ उसकी रील भी है। अदालत ने आरोपियों को हिरासत में भेज दिया है।

एआईएडीएमके में फूट तमिलनाडु में 'खेला'

● बागी गुट का टीवीके को समर्थन का ऐलान

षणमुगम ने कहा-जनादेश विजय के साथ है

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में दो हिस्सों में टूट गई है। पार्टी के नेता सीवी षणमुगम ने सीएम विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) को समर्थन देने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि उनके साथ 30 विधायकों ने भी विजय को समर्थन देना स्वीकार किया है। मंगलवार सुबह षणमुगम ने बयान दिया, 'हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। यह जनादेश टीवीके के लिए

नहीं, विजय के लिए है। इसलिए हम टीवीके सरकार को अपना समर्थन देते हैं। अगर हम डीएमके के साथ गठबंधन करते तो एआईएडीएमके का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता।' षणमुगम ने यह भी कहा- मेरी एआईएडीएमके तोड़ने की कोई मंशा नहीं है।

हमारा पूरा फोकस पार्टी को दोबारा मजबूत करने पर

षणमुगम ने कहा- हमने एआईएडीएमके की स्थापना डीएमके के खिलाफ की थी। 53 सालों से हमारी राजनीति डीएमके के खिलाफ रही है। इसे देखते हुए एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि डीएमके के समर्थन से एआईएडीएमके की सरकार बनाई जाए। हालांकि, हमारे ज्यादातर सदस्यों ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसका विरोध किया। अगर हम डीएमके के साथ गठबंधन करते तो एआईएडीएमके का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। षणमुगम ने ये भी कहा कि हम अभी बिना किसी गठबंधन के खड़े हैं और अब हमारा ध्यान अपनी पार्टी को फिर से मजबूत और जीवंत बनाने पर होना चाहिए।

कूनो में 4 चीता शावकों की मौत, शव खाए मिले

श्योपुर में शिकार की आशंका, एक महीने पहले हुआ जन्म; मांद के पास पड़े मिले

श्योपुर (नप्र)। श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता केजीपी 12 के चार शावकों की मौत हो गई। मंगलवार सुबह मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट (मांद) के पास चारों शावकों के शव मिले। वन विभाग के मुताबिक शव आंशिक रूप से खाए हुए थे, जिससे किसी जंगली जानवर के शिकार की आशंका जताई जा रही है।

मादा चीता पूरी तरह स्वस्थ- शावकों का जन्म 11 अप्रैल 2026 को हुआ था और वे करीब एक महीने के थे। टीम ने उन्हें 11 मई की शाम आखिरी बार जीवित देखा था। मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा।

वन विभाग ने बताया कि मादा चीता केजीपी 12 पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। कूनो में अब 50 चीते बचे हैं, जिनमें 33 भारत में जन्मे चीते हैं।

भोपाल प्रेस क्लब ने हर्षोल्लास से मनाया जन्मदिन

भोपाल। भोपाल प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार हाकम सिंह गुर्जर का जन्मदिन हर्षोल्लास और आत्मीय माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकार साथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित, सतीश सक्सेना, नासिर हुसैन, अलीम बज्मी, देशदीप सक्सेना, संजय सक्सेना, सलमान रावी, अभिनव गोयल, गोपाल जैन, प्रकाश सक्सेना, डी.एन. पांडे, नासिर अली, ओ.पी. श्रीवास्तव, रूपेश गुप्ता, विनोद तोमर एवं विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा लखन सिंह मीणा, बलवीर यादव, जगदीश यादव, भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री कप्तान यादव, तनवीर, अनवर मेव, डॉ. योगेंद्र मुखरेया एवं पिंटू तिवारी सहित अनेक पत्रकार साथियों और नेताओं ने शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

वर्चस्व की जंग में टूटी 'पुजारी' के गर्दन की हड्डी

उमरिया (नप्र)। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आई है। रिजर्व का सबसे टूरिस्ट फ्रेंडली और फोटो खिंचवाने का शौकीन नौ साल का नर बाघ, जिसे लोग प्यार से पुजारी बुलाते थे, एक टेरिटोरियल फाइट में मारा गया है। सोमवार सुबह खितौली रेंज के धमधामा इलाके में दो बाघों के बीच हुई इस भिड़ंत ने रिजर्व के एक मशहूर सितारे का अंत कर दिया।

सुबह 6.30 बजे गूंजी दहाड़- वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 6.30 बजे खितौली रेंज के सुरक्षाकर्मियों ने बाघों के लड़ने की भयानक आवाजें सुनी थीं। सूचना मिलते ही गश्ती दल ने इलाके की घेराबंदी की और सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद जंगल में एक बाघ का शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच में बाघ के शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, लेकिन सभी अंग सुरक्षित होने के कारण शिकार की आशंका को खारिज कर दिया गया है।

वर्चस्व की जंग में टूटी गर्दन की हड्डी- बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि मृत बाघ पुजारी की गर्दन की हड्डी टूट गई थी और शरीर पर पंक्चर के निशान थे। आशंका है कि पुजारी और बाघ 'डी1' के बीच भीषण लड़ाई हुई, क्योंकि दोनों एक ही इलाके में रहते थे। पुजारी अपनी मिलनसार प्रकृति के लिए जाना जाता था और अक्सर पर्यटकों की जिप्सियों के सामने निडर होकर पोज देता था।

मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का बढ़ता ग्राफ- पुजारी की मौत के साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न अभयारण्यों में इस साल मरने वाले बाघों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। यह आंकड़ा वन्यजीव संरक्षण की चुनौतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। घटना के बाद इलाके में एलीफेंट पेट्रोलिंग टीम, डॉग स्क्वायड और मेटल डिटेक्टर टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अन्य साजिश की संभावना की गहन जांच की जा सके।

सोशल मीडिया, हनीट्रैप और पैसों के जाल में 'हिंदू चेहरे'

● यूपी में धर्मांतरण से लेकर टेरर मॉड्यूल तक से जुड़े तार

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में बीते पंच वर्षों के दौरान एटीएस और पुलिस की कार्रवाई में एक नया और खतरनाक पैटर्न सामने आया है।

विदेशी फंडिंग, सोशल मीडिया के जरिए ब्रेनवॉश, हनीट्रैप और आर्थिक लालच के सहारे पहले धर्मांतरण करवाया गया और फिर इन्हीं लोगों को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। कई मामलों में ऐसे नेटवर्क का 'फेस' हिंदू नामों वाले युवा बनाए गए। हाल ही में पकड़े गए दो

अलग-अलग मॉड्यूल इसकी ताजा मिसाल हैं। एक मामले में तुषार नामक युवक हिजबुल्लाह की पहचान और बाराबंकी का कृष्णा मिश्रा आईएसआई से जुड़कर आतंकी साजिशें रच रहे थे।

2021 में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी

वर्ष 2021 में यूपी का अब तक का सबसे बड़ा धर्मांतरण केस सामने आया, जब एटीएस ने उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि करोड़ों की विदेशी फंडिंग के जरिए इस्लामिक दावा सेंटर के नाम पर मूक-बधिर छात्रों और अर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी, पैसे और शादी का लालच देकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया गया। इसी कड़ी में 2021 में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी भी हुई, जो कथित तौर पर ट्रस्ट और एनजीओ के जरिए अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था।

जलालुद्दीन उर्फ छांगुर कनेक्शन

आरोप है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने विदेश से आए नीतू और नवीन वोहरा का धर्मांतरण करवाने के बाद उन्हें सामने रखकर विदेशी फंडिंग के जरिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया। इस पूरे नेटवर्क का फेस नीतू और नवीन बनाए गए। इसके बाद आगरा पुलिस ने 2025 में एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया। दो बहनों के लापता होने से शुरू हुई जांच में रेडिकलाइजेशन, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें और अमेरिका-कनाडा से फंडिंग के सुराग सामने आए। इस रैकेट में कई ऐसे लोग शामिल थे, जो धर्मांतरण के बाद मुस्लिम बने और हिंदू युवक-युवतियों को फंसाकर उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलने की भूमिका निभा रहे थे। ये नेटवर्क तीन-स्तरीय रणनीति पर काम करते है, पहले भावनात्मक और डिजिटल जाल, फिर आर्थिक लालच या दबाव।

26 घंटे में 3 हत्याएं करने वाला साइको किलर ढेर

● यूपी पुलिस बोली-आरोपी ने पिस्तौल छीनकर फायरिंग की, एनकाउंटर में मारा गया

चंदौली (एजेंसी)। यूपी में चलती ट्रेन और अस्पताल में तीन हत्याएं करने वाला साइको किलर सोमवार रात 12 बजे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। चंदौली एसपी आकाश पटेल ने बताया- पुलिस आरोपी को क्राइम सीन रीक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी। इसी दौरान उसने पुलिस अफसर की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसे सिर और सीने में गोली लग गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुठभेड़ शहर से 15 किमी दूर दरियापुर रेलवे लाइन के पास हुई। इसमें दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सेना से रिटायर साइको किलर गुरप्रीत सिंह (45) पंजाब का रहने वाला था। उसने चंदौली में 26 घंटे के भीतर बेवजह तीन हत्याएं की थीं। तीनों वारदातों का पैटर्न एक जैसा था- गोली सीधे कनपटी पर मारी गई थी।

गुरप्रीत सिंह, आरोपी

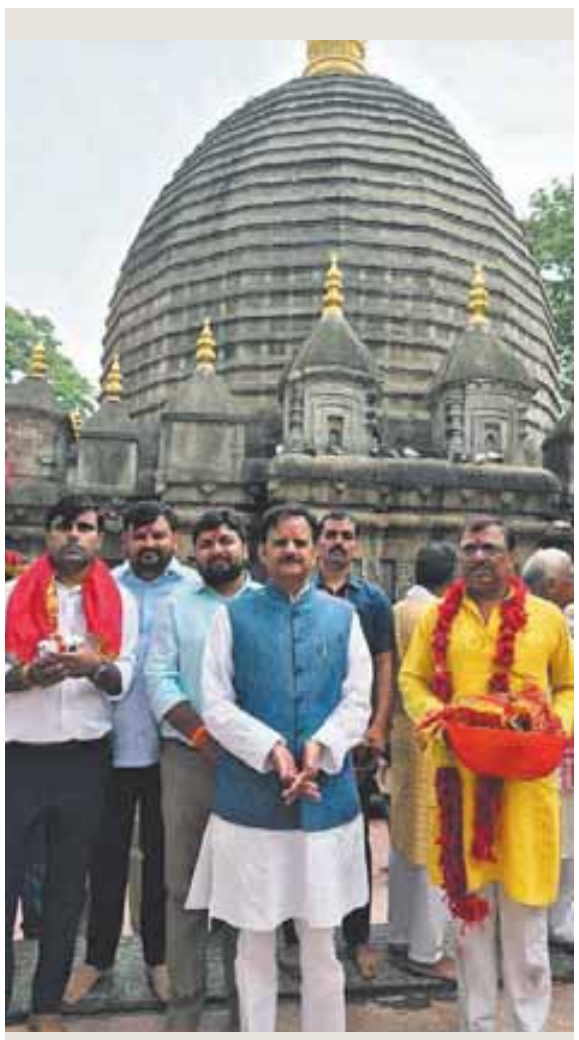

सौर ऊर्जा अपनाएं, भविष्य बचाएं

शासकीय भवनों में रेस्को मॉडल से सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूकता जरूरी : मंत्री श्री शुक्ला

जिला पंचायत भोपाल में शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के मध्य हुए विद्युत क्रय अनुबंध

भोपाल (नप्र)। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निरंतर ईंधन (फ्यूल) और ऊर्जा बचाने का आह्वान किया गया है। हमें दृढ़ संकल्प के साथ इस दिशा में काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप शासन और प्रशासन को एक साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट होना होगा। मंत्री श्री शुक्ला मंगलवार को जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में प्रदेश के विभिन्न विभागों के शासकीय भवनों में सोलर रूफ़टॉप संयंत्र स्थापना के लिये शासकीय संस्थाओं व रेस्को विकासक इकाइयों के मध्य विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री शुक्ला ने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि हमारी 50 प्रतिशत ऊर्जा खपत नवकरणीय ऊर्जा से होनी चाहिए और मध्यप्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आमजनों में जागरूकता लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आने वाले समय में हर घर की छत पर सोलर पैनल नजर आने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि कि रेस्को पद्धति के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में समय पर भुगतान एवं उचित मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाएं।

रेस्को एक महत्वपूर्ण बचत योजना- अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने कहा कि रेस्को योजना शून्य निवेश, पहले दिन से बचत और नेट जीरो की ओर बढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। यह शासन के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। उन्होंने कहा कि यह एक साझेदारी का प्रोजेक्ट है, इसलिए सभी संबंधित विभागों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे।

समय पर भुगतान पर मिलेगी छूट

प्रबंध संचालक श्री अमनबीर सिंह बैंस ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रेस्को पद्धति से 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली जनरेट होगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्परता से बेहतर प्रबंध कर कार्य करने के निर्देश दिए। एमडी श्री बैंस ने बताया कि बिजली बिलों का भुगतान 3 से 10 तारीख के बीच करने पर भुगतान राशि में 1 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है, जबकि देरी से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की पेनल्टी लगाई जाएगी।

शासकीय कार्यालय बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण में बनेंगे सहभागी

योजना के सफल एवं दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश निश्चित रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। शासकीय कार्यालय इस मॉडल को अपनाकर न केवल आर्थिक बचत करेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना अहम योगदान देंगे। बैठक में कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती इला तिवारी एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर में किया दर्शन एवं पूजन

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने असम स्थित पावन शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन एवं पूजन किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि दिव्य धाम अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा और दैवीय चेतना से परिपूर्ण है, जिसकी अनुभूति मन आत्मा को अपार शांति प्रदान करती है। उन्होंने मां कामाख्या से समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की।

अस्पताल में इलाज ही नहीं, मरीज की थाली भी हुई महंगी

दवा और बेड के साथ अब खाने के बिल ने छुड़ाए पसीने

भोपाल (नप्र)। कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में अब बीमार पड़ना भी किसी बड़ी आर्थिक मुसीबत से कम नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अस्पतालों का खर्च तेजी से बढ़ा है। इलाज और दवाओं के बढ़ते दामों के बीच अब मरीजों के दैनिक भोजन यानी 'पेशेंट डाइट' पर भी महंगाई की गाज गिरी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुए इजाफे के कारण अस्पतालों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है।

थाली की कीमत में 16.7 प्रतिशत का उछाल- एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने बताया कि नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स (एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में पेशेंट थाली की कीमत, जो पहले 120 रुपये थी, अब बढ़कर 140 रुपये हो गई है। यह सीधी तौर पर 16.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। यह उन मरीजों के लिए बड़ा झटका है जो आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते और प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज खुद के खर्च पर करा रहे हैं।

सिर्फ गैस ही नहीं, बिजली और बैकअप भी महंगे- अस्पताल संचालकों का तर्क है कि केवल रसोई गैस ही नहीं, बल्कि बिजली की दरें, बैकअप पावर सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन और परिवहन लागत बढ़ने से भी स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हुई हैं। गोविंदपुरा स्थित एक निजी अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के कारण कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन लंबे समय तक बढ़ी हुई लागत को खुद वहन करना मुश्किल होगा।

मध्यम और निम्न आय वर्ग पर दोहरी मार

महंगाई का सबसे बुरा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जो पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं। बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने और दवाओं के बढ़ते खर्च ने कई परिवारों को कर्ज लेने या अपनी बचत खत्म करने पर मजबूर कर दिया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में भी टेस्ट, दवाइयों और परिवहन पर होने वाला खर्च आम आदमी की कमर तोड़ रहा है।

अशोका गार्डन में छात्रा ने ब्लेड से हाथ की नस काटी, मौत

मां घर से बाहर गई थी; खजूरी सड़क इलाके में अस्पताल अटेंडर ने लगाई फांसी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में बीए की छात्रा ने ब्लेड से हाथ की नस काटकर जान दे दी। वहीं, खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में 23 साल के अस्पताल अटेंडर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

मां के बाहर जाते ही छात्रा ने उठाया कदम

अशोका गार्डन थाना पुलिस के मुताबिक ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय ख्याति जैन बीए की छात्रा थी। उसके माता-पिता का करीब 10 साल पहले तलाक हो चुका था और वह अपनी मां के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को उसकी मां किसी काम से बाहर गई हुई थी। इसी दौरान ख्याति ने ब्लेड से हाथ की नस काट ली। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई।

मोबाइल जब्त कर जांच शुरू- सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। कमरे की तलाशी के दौरान कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के बयान अभी दर्ज नहीं हो सके हैं।

दिग्विजय सिंह की 24 साल पुरानी नोटशीट बनी मुसीबत

मुख्य सूचना आयुक्त ने मांगी फाइल, अफसरों को किया तलब; रीवा की अनुदान प्राप्त स्कूल का मामला

भोपाल (नप्र)। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा वर्ष 2002 में लिखी गई एक नोटशीट अब स्कूल शिक्षा विभाग के लिए परेशानी का कारण बन गई है। रीवा जिले के एक अनुदान प्राप्त विद्यालय से जुड़ी इस नोटशीट की जानकारी विभाग आरटीआई में उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों को भोपाल तलब कर लिया है। मामला रीवा जिले की त्यौंथर तहसील स्थित जनता हायर सेकेंडरी स्कूल मांगी से जुड़ा है। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव ने मंगलवार को इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय के अधिकारियों, लोक शिक्षण आयुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों को उपस्थित होने के निर्देश दिए।

सरकारी घोषित करने के दिए थे निर्देश- दरअसल, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 3 अप्रैल 2002 को नोटशीट क्रमांक 1240/02 पर टीप लिखते हुए कहा था कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांगी वर्ष 1973 से संचालित है और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इसका शासकीय होना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यालय को शासकीय घोषित करने के आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे। बताया जाता है कि उस समय के स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने भी इस नोटशीट पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए थे। हालांकि अब विभाग इस महत्वपूर्ण नोटशीट और उससे जुड़ी फाइल का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पा रहा है।

आरटीआई के तहत मांगी थी जानकारी

विद्यालय में पदस्थ रहे सेवानिवृत्त शिक्षक तुंगनाथ द्विवेदी ने आरटीआई के तहत इस फाइल की जानकारी मांगी थी। आरोप है कि विभाग ने पहले जानकारी नहीं दी, जिसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा। अब आयोग की सख्ती के बाद विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए हैं।

सूत्रों के अनुसार यदि यह नोटशीट और संबंधित फाइल प्रक्रिया में आगे बढ़ती तो जनता हायर सेकेंडरी स्कूल मांगी को वर्षों पहले शासकीय दर्जा मिल सकता था। आरोप यह भी है कि उस समय विभाग के कुछ अधिकारियों और स्थानीय नेताओं की वजह से फाइल को दबा दिया गया। वर्तमान में विद्यालय की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। स्कूल में केवल एक शिक्षक पदस्थ है और आने वाले समय में विद्यालय शिक्षक विहीन होने की आशंका जताई जा रही है।

मप्र में राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव की वोटिंग

88 हजार वकील करेंगे मतदान, भोपाल से 20 प्रत्याशी मैदान में

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान कराया जा रहा है। भोपाल में मतदान जिला न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में मध्य प्रदेश से कुल 122 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं, भोपाल से 20 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 18 पुरुष और 7 महिला सदस्यों का चयन किया जाएगा।

88 हजार अधिवक्ता करेंगे मतदान- प्रदेशभर में लगभग 88,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा चुनाव- मुख्य मतदान अधिकारी मनोहर लाल पाटीदार ने बताया कि यह चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में हो रहा है। इसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन भी किया गया है।

भोपाल के प्रमुख प्रत्याशी चर्चा में- भोपाल से निर्वतमान को-चेयरमैन विजय चौधरी, पूर्व को-चेयरमैन मो. महबूब अंसारी, राजेश व्यास, पीसी कोठारी और चन्द्रकुमार वलेजा सहित कई प्रत्याशी चर्चा में हैं।

पहचान पत्र अनिवार्य किया गया- मतदान के लिए अधिवक्ताओं को राज्य अधिवक्ता परिषद या जिला बार संघ द्वारा जारी पहचान पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। बिना पहचान पत्र मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

न्यायालयों में अवकाश घोषित- मतदान को देखते हुए राज्य के सभी न्यायालयों को कार्यमुक्त घोषित किया गया है। न्यायाधीश और न्यायिक कर्मचारी भी मतदान प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। अपर जिला न्यायाधीश मनोहर लाल पाटीदार को मतदान अधिकारी बनाया गया है। उनके निर्देशन में पूरी मतदान प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है।

अशोका गार्डन में पिता ने बेटे पर फायर किया

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता ने अपने ही 16 वर्षीय बेटे पर लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से फायर कर दिया। घटना सोमवार रात करीब 10:45 बजे एकता पुरी इलाके में हुई। गनीमत रही कि गोली किशोर को नहीं लगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर बंदूक व कारतूस जब्त कर लिए। अशोका गार्डन थाने के सब इंस्पेक्टर ओमकार सिंह के मुताबिक एकता पुरी निवासी 16 वर्षीय राज चौरसिया उर्फ बंटी चौरसिया कक्षा 11वीं का छात्र है। उसकी मां घरों में साफ-सफाई का काम करती है, जबकि पिता अलग रहता है।

भोपाल से श्रीनगर, चेन्नई-केरल के लिए उड़ेंगे प्लेन

भोपाल (नप्र)। अगले कुछ महीनों में भोपाल एयरपोर्ट से श्रीनगर, चेन्नई, केरल, देहरादून, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़-जम्मू समेत अन्य बड़े शहरों के लिए प्लेन उड़ सकते हैं। सांसद आलोक शर्मा की मीटिंग के बाद सरकार ने एयरलाइंस ऑपरेटरों से प्रपोजल मांगें हैं।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी है। जिसमें आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रापोजल मांगे गए हैं। कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन ने आरएफपी जारी कर शेड्यूल एयरलाइन ऑपरेटरों को भोपाल एवं मध्यप्रदेश के अन्य हवाई अड्डों से प्रमुख घरेलू एवं

अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधी उड़ान सेवाएं प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इन शहरों के लिए उड़ानें हो सकती हैं शुरू- भोपाल विमानतल सलाहकार समिति के सदस्य मनोज मीक ने बताया राजा भोज एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठकों में यह सुझाव मिले थे कि भोपाल से चेन्नई, कोलकाता, गोवा, जयपुर, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून, केरल और अन्य प्रमुख शहरों के लिए बेहतर उड़ान सेवाएं जरूरी हैं। अब एमपी सरकार ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की पहल की है। इससे एयरलाइंस को भोपाल जैसे संभावनाशील केंद्र से जुड़ने का ठोस आधार मिलेगा।

भोपाल में युवक को चाकू मारा, पेट की आंतें निकलीं

बाइक टकराने के विवाद में बीच-बचाव करने गया था; बदमाशों ने उसी पर हमला कर दिया

भोपाल (नप्र)। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में बाइक टकराने के विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार रात की थी। युवक ने मंगलवार तड़के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार रासलाखेड़ी निवासी अजय लोधी (20) प्राइवेट जॉब करता था। रविवार शाम करीब 7:30 बजे उसके चचेरे भाई नितिन लोधी की बाइक राम मंदिर के पास एक नाबालिग से टकरा गई थी। नाबालिग सबरी नगर में आयोजित माता पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आया था।

बाइक टकराने पर नाबालिग के साथ आए दीपक ठाकुर और उसके साथियों ने नितिन से विवाद किया। सूचना मिलने पर अजय लोधी मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव किया। इस दौरान दीपक ने उसे धमकी दी।

रात में फिर हुआ आमना-सामना- इस विवाद के कुछ देर बाद ही रासलाखेड़ी इलाके में दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। यहां दोनों ओर से मारपीट हुई। इसी दौरान दीपक ठाकुर ने साथियों के साथ मिलकर अजय लोधी पर चाकू से हमला कर दिया।

चाकू अजय के पेट में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी आंते बाहर आ गई थीं। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मंगलवार तड़के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

हत्या का केस दर्ज, दो गिरफ्तार- छोला मंदिर थाना पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। युवक की मौत के बाद धारा बढ़ाकर हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक ठाकुर और उसके एक साथी को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है।

भिंड के दंदरौआ धाम के पास, पेड़ से टकराकर पलटा वाहन

पिता-पुत्र समेत 3 की मौत, दो गंभीर

भिंड (नप्र)। भिंड में मंगलवार तड़के सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा दंदरौआ धाम गेट नंबर-1 के पास हुआ।

मेहगांव थाना पुलिस के मुताबिक, मौ क्षेत्र से पांच लोग एक लोडिंग वाहन में सवार होकर दंदरौआ की ओर जा रहे थे। वाहन में एक भैंस भी लदी हुई थी। मेहगांव-मौ मुख्य मार्ग पर दंदरौआ धाम गेट नंबर-1 के पास पहुंचते ही चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार वाहन सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय प्रीतम मांझी, उनके पुत्र सुनील मांझी (दोनों निवासी ग्राम छोली, जिला ग्वालियर) और उपेंद्र राणा (निवासी लखनौती, डबरा जिला ग्वालियर) के रूप में हुई है।

गंभीर रूप से घायल दो लोग ग्वालियर रेफर

हादसे में रामरूप बघेल निवासी एरोली और मानवेंद्र ठाकुर घायल हैं। सूचना मिलते ही मेहगांव थाना पुलिस पहुंची। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। एसडीओपी संजय कोच्छा ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

संपादकीय

देश में बढ़ते अपराध

देश में अपहरण और जबरन उठाकर ले जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। जिस रफ्तार से यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, उससे लगता है कि पुलिस और कानून का कोई खौफ अपराधियो में बचा ही नहीं है। टैक्नालॉजी ऐसे अपराधों की वृद्धि में मदद ही कर रही है। बुजुर्गों पर अत्याचार के मामले में मप्र देश में अव्वल रहा है तो यह बेहद चिंता और अफसोस की बात है। खास कर बीते एक दशक में ऐसी घटनाओं में अप्रत्याशित उछाल आया है। हाल ही में भोपाल में एक आईएएस एकेडमी की निदेशक के अपहरण और 1.89 करोड़ रुपए की फिरौती के मामले ने देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 1953 से 2024 के बीच देश में कुल 20 लाख से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन सात दशकों के कुल मामलों का 54% हिस्सा (11.24 लाख केस) केवल पिछले 11 वर्षों (2013-2024) में दर्ज हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल अपराधों में अपहरण की हिस्सेदारी 1953-62 में 1.01% थी, जो 2013-24 के दौरान बढ़कर 3.04% तक पहुंच गई है। अपहरण के पीछे सबसे बड़ा कारणों में विवाह के लिए महिलाओं का उठाना और सामान्य अपहरण है। इसके अलावा प्रेम प्रसंग भी इसका एक कारण है। हालांकि फिरौती के लिए किए जाने वाले संगठित अपहरण कुल मामलों का केवल 0.7% ही हैं। राज्यों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे स्थान पर रहा करता था, लेकिन 2024 के आंकड़ों में बिहार शीर्ष छह राज्यों में सबसे नीचे दर्ज किया गया है। एक और चिंता की बात चाइल्ड पोर्न है। भारत में बच्चों के खिलाफ दर्ज साइबर अपराधों में करीब 10 में से 9 मामलों में बच्चों से जुड़ा यौन रूप से अश्लील कंटेंट पब्लिश या ट्रांसमिट करने की बात सामने आई है। हालांकि एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल अपराध घटने के बावजूद बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,87,702 मामले दर्ज हुए। यह जो 2023 के 1,77,335 मामलों से 5.8% ज्यादा हैं। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी साल 2024 की क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में शीर्ष पर रही है। 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,396 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 में 13,366 थे। तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे हैं। 2024 में महिलाओं के खिलाफ 4,41,534 मामले दर्ज हुए, जो 2023 से 1.5% कम थे। सबसे अधिक 27.2% मामले पति के क्रूरता और अपहरण से संबंधित थे। दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ 1267 अपराध दर्ज किए गए। दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों की दर प्रति लाख आबादी पर 110 मामले रही, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा दरों में से एक रही। मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा, जहां 2024 में 5,875 मामले दर्ज किए गए, यह संख्या 2023 के 5,738 मामलों से ज्यादा है। दूसरी तरफ, देश में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। 2024 में कुल 32,602 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 के मुकाबले 16.9% ज्यादा हैं। जरूरत इस बात की है कि सभी तरह के अपराधों पर सख्ती से लगाम कैसे लगाई जाए, पर गंभीरतापूर्वक विचार तद्नुसार योजना बनाकर उस पर सख्ती से अमल किया जाए। अगर आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो सुशासन का कोई अर्थ नहीं है।

भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन: उत्थान और पतन की अकथ-कथा

नजरिया

डॉ. सुधीर सक्सेना
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

शुरूआत सचमुच शानदार थी। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था; दमन, शोषण और दीनता का शिकार दास राष्ट्र। महात्मा गांधी विश्व-इतिहास के अलीक-योद्धा के तौर पर परिदृश्य में उभर रहे थे। सारा राष्ट्र आजादी के लिये व्यग्र था। ऐसे में एक नये वैचारिक-आंदोलन ने भारत में प्रवेश किया और सर्वथा अलहदा मिजाज की एक पार्टी ने भारत में जन्म लिया। इसमें केन्द्रीय और अग्रणी भूमिका थी एमएन राय यानि मानवेंद्र नाथ राय की, जिन्हें सोवियत संघ जैसे विशाल राष्ट्र के सर्वेसर्वा बलादिमीर इलिच लेनिन का संग-साथ और विश्वास हासिल था। हुआ यह कि 17 अक्टूबर, सन् 1920 को पामीर पार ताशकंद में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस की बैठक हुई और इसने भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की पूर्वपीठिका रच दी। विचार मंथन और सांगठनिक प्रयासों के बाद अंततः 25 दिसंबर, सन् 1925 को भारत के मैनचेस्टर कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इसके शुरूआती नेताओं में एमएन राय के अलावा अबनि मुखर्जी, मोहम्मद अली और शफीक सिद्दिकी प्रमुख थे।

25 दिसंबर, सन् 2025 से काल गणना करें तो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की एक सदी पूरी हो चुकी है। इस मान से यदि एक शती के वृत्तांत यानि कम्युनिस्ट आंदोलन के हश्र को बांचें तो बहुत दिलचस्प चटख और धूमिल रंगों का कोलाज उभरता है। बालीवुड की फिल्म की तर्ज पर हम इसे राइज एण्ड फाल आफ कम्युनिस्ट मूवमेंट-कम्युनिस्ट आंदोलन का उत्थान और पतन भी कह सकते हैं। इस वृत्तांत में लंबे रक्तिम संघर्ष हैं और गर्वीली सफलतायें भी। वहां विफलतायें हैं और बिखराव भी। वहां विमर्श है और विभ्रम भी। संघर्ष, निष्ठा, समर्पण, बलिदान और अनेक महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद इसकी अंततः शोकांतिका में परिणिति विस्मयकारी है, जो बहुतों को शोकाकुल करती है, तो बहुतों को हर्षित भी। क्या वजह है कि ऐसा हुआ? क्या ऐसा होना वृहत्तर समाज के स्वास्थ्य और भविष्य के लिहाज से सुखद है अथवा इसे विडंबना या त्रासदी माना जाये।

विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन और भारत के रिश्तों से शुरू करें तो कई अहम निष्कर्ष निकलते हैं। आंदोलन के प्रणेता कार्ल मार्क्स पहले मनीषी हैं, जिसने सन 1857 के अंग्रेजों द्वारा प्रचारित गदर को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। मार्क्स की भारत के इतिहास में गहरी रूचि थी और वह भारत की आजादी के हिमायती थे। इसमें कोई शक नहीं कि बीसवीं सदी विश्व स्तर पर वाम विचारों की सदी थी और इसने सभी महाद्वीपों में करोड़ों लोगों को वैचारिक तौर पर प्रभावित और आंदोलित किया। श्रमिकों, लेखकों और कलाकारों पर इसका प्रभाव अभूतपूर्व था। श्रम की महत्ता और गरिमा का पाठ प्रस्तुत कर इसने अनेक देशों में कू-दे-ता (तख्तापलट) की स्थितियां पैदा कीं; साहित्य कला और संस्कृति में नये आंदोलन उपजाये, पूंजीवादी-ईमान को डगमग किया, श्रमिकों के लिए बेहतर वातावरण सृजित किया, पारंपरिक रूढ़ियों के प्रति असंतोष उपजाया, उपनिवेशवाद के खिलाफ अलख जगाई और युवा वर्ग की आंखों में नये सपने आंजे। उसने गैर-बराबरी के खिलाफ बराबरी, शोषण के खिलाफ मुक्ति और दासता के खिलाफ स्वतंत्रता की हिमायत की। यह विश्व इतिहास में परंपरा और रूढ़ियों के खिलाफ विचलन और हस्तक्षेप का सर्वथा भिन्न और अपूर्व उपक्रम था। हम स्तालिन, गोर्की, चेखव, माओ, होची मिन्ह, चेग्वेरा, कास्त्रो, नाजिम, हिकमत, फैज, रेजिस द ब्रे, चार्ली चैप्लिन आदि की बात न कर यदि भारतीय परिदृश्य पर भी दृष्टिपात करें तो बड़े और सितारा नेताओं, कवियों, कलाकारों, दार्शनिकों और कार्यकर्ताओं में कौन है, जिसे सोवियत क्रांति अथवा साम्यवादी विचारों व आंदोलनों ने प्रभावित नहीं किया? पं. नेहरू से लेकर भगत सिंह तक, रबींद्रनाथ ठाकुर से लेकर प्रेमचंद तक, राजकपूर से लेकर बलराज साहनी तक, माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी तक नामों की एक अछोर कतार है, जिन्हें साम्यवादी विचारों ने आलोड़ित किया। शहीदे आजम भगत सिंह तो फांसी के तख्ते की ओर जाने से कुछ क्षण पहले तक लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे....

और लेनिन? लेनिन तब नहीं थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि लेनिन क्या थे? लेनिन भारत से गेहरे प्रेम में डूबी हुई - महान क्रांतिकारी शख्सियत थे। उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में लिखा, जालियांवाला कांड की निंदा की, तिलक को मांडले जेल भेजन का विरोध किया, महात्मा गांधी की अगुवाई में आजादी की लड़ाई का समर्थन किया, भारत में अकाल पर अंग्रेज-नीतियों की निंदा की और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी समेत सैकड़ों युवकों के विचारों को प्रज्वलित किया।

निश्चित ही, लेनिन अपने प्रति भारतवासियों के बेहतर सोच और सलूक के हकदार हैं। बाद के दौर को देखें तो भी सोवियत और फिर रूस के शासक और जन भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और सदिच्छा रखते हैं। चाहे बुल्गानिन, ब्रेभनेव, खुश्चेव और कोसीगिन रहे हों या फिर पुतिन। बावजूद इन संदर्भों के भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन बिखरता गया। उन्होंने यत्नपूर्वक ट्रेड यूनियनों को संगठित किया, इंडियन कॉफी हाऊस जैसे दर्जनों संस्थाओं के हेतु बने, सन् 1957 में केरल में पहली निर्वाचित सरकार का गठन हुआ, पश्चिम बंगाल में कई दहाइयां उनके लाल झंडे के तले बीतीं, देवेगौड़ा और गुजराल की केन्द्रीय सरकारों में उनकी भागीदारी रही, साहित्य और कला के लोक में उनकी केंद्रीय इयत्ता रही, लेकिन मोटे तौर पर बीती पाव सदी में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का शीराजा बिखरता गया। क्यों?

भारत में कम्युनिस्टों का इतिहास आंदोलनों का इतिहास है। आंदोलन यानि संघर्ष। संघर्ष यानि विचलन। विचलन यानि मौजूदा स्वरूप, मौजूदा ढांचे मौजूदा समीकरणों के स्थान पर नया स्वरूप, नया ढांचा, नये समीकरण। यानि परिवर्तन। यथास्थिति नहीं, बदलाव। जड़त्व नहीं गतिज। नयी वैचारिकी। नया उन्मेष। अब परंपरा के सन्दर्भ में इन परिवर्तनों की भूमिका पर गौर करें। एक बंद रूढ़िग्रस्त समाज में ग्लासनोस्त (खुलापन) और पिरिस्त्रोइका (पुनर्रचना) की जरूरत, उसके प्रति पारंपरिक सोच और तज्जन्य प्रतिकार पर तवज्जो दें। हश्र के वजूहात स्पष्ट हैं। जहां परिवर्तन के बजाय परंपरा श्रेष्ठ और श्रेयस्कर हो, वहां आप कब तक और कहां तक जूझेंगे? संघर्ष जब थकता है, तो सुविधा मांगता है। हर कौम, नस्ल और समाज का अपना डीएनए होता है। भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा को 'देशी बागीचे में विदेशी बेल' या विजातीय प्रजाति माना गया। रूपक गढ़ा गया कि जब मस्का में बारिश होती है तो भारत में कम्युनिस्ट अपनी छतरियां खोल लेते हैं। यह नैरेटिव भी पनपा कि भारतीय कम्युनिस्टों का रिमोट कंट्रोल मस्क्वा और बीजिंग के हाथों में है। भारत में कम्युनिस्टों की विफलता का एक बड़ा मुद्दा उनकी धार्मिक सोच भी रहा। एक धर्मप्राण राष्ट्र में धर्म को अफीम बताना लोगों के गले नहीं उतरा। यह बात भी घर-घर फैलाई गई कि कम्युनिस्ट राज में तो सब कुछ सरकारी है। नौकरी भी और बच्चे भी। कम्युनिस्ट आयेंगे तो मंदिर बंद हो जायेंगे और बच्चों को सरकार छीन लेगी। और आपकी संपत्ति भी आपकी नहीं होगी। स्पष्ट है कि ये 'नैरेटिव' काम कर गये। एक धर्मप्राण आस्था से परंपराजीवी महादेश में परिवर्तन के ध्वजवाहक सफलता की पताकायें कहां फहराते? मेरा निजी अनुभव है कि परंपरा पोषक कर्मकाण्डी घरों में 'साला कम्युनिस्ट' गाली की तरह इस्तेमाल होने लगा। भारतीय समाज में वैसे भी तर्क के लिये कम ठौर रहा है। कम्युनिस्टों की गलती रही या मूर्खता कि वे साम्यवादी सोच या विचारधारा को भारतीय या देशज शब्दावली और सांचे में नहीं ढाल सके और कई बार उन्होंने राष्ट्रीय परिस्थितियों को नजरंदाज कर तदनुरूप निर्णय लेने के बजाय 'ऊपरी' निर्देश पर फैसले किये। वे बूर्ज्वा, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा की आयातित शब्दावली में उलझे रहे। नतीजतन उनका दायरा सीमित रहा। वे अंदरूनी इलाकों या वृहत्तर भूभाग में जमीन नहीं गोड़ सके।

ऐसा नहीं है कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की पंजी में चमकीली घटनाएं या चेहरे नहीं हैं। आज की दलदली राजनीति में कम्युनिस्ट नेता ही हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोपों से कभी नहीं बिंधे। ज्योति बसु का प्रधानमंत्री बनने से इंकार भारतीय राजनीति की विरल घटना है। भारत में जब भी आंदोलनों का इतिहास लिखा जायेगा, तेभागा और तेलंगाना आंदोलन, नलगोंडा, वारंगल और खम्मम का कर्ज माफी आंदोलन, नक्सलबाड़ी संघर्ष का भी जिक्र होगा। इसी विचार ने हमें इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो, हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, रोटी कपड़ा लेकर रहेंगे जैसे नारे दिये। इसी ने हमें हम होंगे कामयाब और वो सुबह कभी तो आयेगी जैसे गीत और साहिर और शैलेन्द्र जैसे अनेक बड़े गीतकार दिये। इसी ने पत्रकारों को श्रमजीवी के खाने में वर्गीकृत किया। कम्युनिस्टों ने हमें नंबूदरीपाद, बीटी रणदिवे, एके गोपालन, श्रीपाद अमृत डांगे, पीसी जोशी, अजय घोष, हरकिशन सुरजीत, ज्योति बसु, अच्युत मेनन, इंद्रजीत गुप्त, प्रकाश कारंत, वृंदा करात, जैसे बेदाग चेहरे दिये। मगर आज कम्युनिस्ट पार्टियों का फलक बेनूर है। वह बार-बार विघटन और विभाजन की भी शिकार रही। कांग्रेस ने उसे पोसा भी और ग्रसा भी। कम्युनिस्ट पश्चिम बंगाल तो पहले ही गँवा चुके थे, चार मई को उनका केरल का अंतिम लाल किला भी ढह गया। भारत नक्सलमुक्त हो चुका है। एक शती के बाद के पहले वर्ष में उनका यह हश्र भारतीय राजनीति का काबिलेगौर अध्याय और पाठ है, लेकिन चीजें लौटती हैं। नये-नये रंग रूपों में। और फिर विचार मरा नहीं करते। वे फीनिक्स पक्षियों की मानिंद होते हैं। परंतु इतिहासजन्य ताजा सच यही है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए भारत की माटी तो मुफीद थी, लेकिन आबोहवा अनुकूल नहीं बैठी।

देश को सशक्त बनाने के पीएम मोदी के पंद्रह सूत्र

आत्मनिर्भर भारत

डॉ. मयंक चतुर्वेदी
लेखक पत्रकार हैं।

भारत आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां वह वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, विदेशी निर्भरता और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे आज पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। भारत भी इनसे बाहर नहीं है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंद्रह सूत्र भारत को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से मज़बूत, पर्यावरणीय रूप से संतुलित और रणनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाने का राष्ट्रीय संकल्प है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कई अवसरों पर कहा है कि '21वीं सदी भारत की सदी होगी', किंतु बड़ा प्रश्न यही है कि यह संभव कैसे होगा? वस्तुतः यह तभी संभव है- जब भारत ऊर्जा, कृषि, उपभोग, परिवहन और जीवनशैली के स्तर पर आत्मनिर्भरता की ओर निर्णायक कदम बढ़ाए, इसलिए पीएम मोदी के आज के समय में दिए गए इन पंद्रह सूत्रों में स्वदेशी, सतत विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और सामूहिक जिम्मेदारी का गहरा संदेश छिपा हुआ है।

विदेशी तेल पर निर्भरता घटाने का राष्ट्रीय अभियान- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। देश अपनी कुल जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इससे हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा भंडार बाहर चला जाता है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, कार-पूलिंग तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर देना अत्यंत दूरदर्शी कदम है। भारत में तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इस दिशा में बड़ा परिवर्तन ला रही है। नीति आयोग के अनुसार यदि भारत बड़े पैमाने पर ई-वाहनों को अपनाता है तो वर्ष 2030 तक अरबों डॉलर के तेल आयात को कम किया जा सकता है।

सार्वजनिक परिवहन- प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने भाषणों में रेलवे ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं। समझना होगा कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों कारण मौजूद हैं। सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे कम ईंधन खर्च करता है और कार्बन उत्सर्जन भी कम करता है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में शामिल है और सरकार इसे ग्रीन ट्रांसपोर्ट में बदलने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।

दिल्ली, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद और अन्य शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार केवल सुविधा का विषय नहीं, बल्कि ऊर्जा बचत और प्रदूषण नियंत्रण का राष्ट्रीय मॉडल है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली मेट्रो हर वर्ष लाखों टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद कर रही है।जब नागरिक निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन अपनाते हैं, तब ट्रैफिक कम होने के साथ ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहता है।

वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल इंडिया- कोविड महामारी के दौरान भारत ने देखा कि डिजिटल तकनीक कैसे लाखों लोगों को घर बैठे कार्य करने में सक्षम बना सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग्स को प्रोत्साहन देना आधुनिक अर्थव्यवस्था की समझ को दर्शाता है।भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है। यह परिवर्तन बताता है कि तकनीक सुविधा होने के साथ ही हम सभी के लिए आर्थिक शक्ति का माध्यम भी है।

स्वदेशी की नई परिभाषा यानी लोकल से ग्लोबल होना है- प्रधानमंत्री मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल' का जो मंत्र दिया, वह बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का आधुनिक रूप है। जूते, बैग, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ और दैनिक उपयोग की सामग्री यदि भारत में बने उत्पादों से खरीदी जाएँ, तब इस स्थिति में घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलना स्वभाविक है।

आज भारत मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है। एक समय भारत मोबाइल आयात करता था, लेकिन अब 'मेडइन इंडिया' स्मार्टफोन दुनिया के अनेक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना ने विनिर्माण क्षेत्र को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी कह भी रहे हैं, 'लोकल उत्पाद खरीदना केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का कार्य है।' वस्तुतः यह विचार भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की बुनियाद है।

विदेशी खर्चों पर नियंत्रण- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गैर-जरूरी विदेश यात्राओं, विदेशी शादियों और विदेश में छुट्टियाँ मनाने से बचने की अपील सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा बचाने से जुड़ी हुई है। भारत हर वर्ष पर्यटन और विलासिता पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करता है। यदि यही धन भारत के भीतर खर्च हो, तो घरेलू पर्यटन, होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय रोजगार को बड़ी मजबूती मिल सकती है। 'देखो अपना देश' अभियान इसी सोच का हिस्सा है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल तक भारत के पास विश्वस्तरीय पर्यटन क्षमता मौजूद है।

सोने की खरीदारी और विदेशी मुद्रा- भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देशों में शामिल है। हर वर्ष हजारों टन सोना आयात किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की यह अपील कि गैर-जरूरी सोने की खरीदारी कम की जाए, वास्तव में आर्थिक संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह सच है कि भारत में सोने को सामाजिक प्रतिष्ठा और निवेश दोनों के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि यही निवेश उत्पादन, स्टार्टअप, कृषि और उद्योगों में जाए, तो अर्थव्यवस्था को अधिक गति मिल सकती है।

खाद्य तेल और स्वास्थ्य- भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करता है। पाम ऑयल और अन्य खाद्य तेलों के आयात पर हर वर्ष भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खाने के तेल का उपयोग कम करने की अपील देखाजाए तो स्वास्थ्य संबंधी सलाह के साथ देश के हित में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि है धरती को बचाने का अभियान- आज अपने सूत्र बिन्दुओं में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग 50 प्रतिशत कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। भारत की मिट्टी लगातार रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से कमजोर हो रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता पर गंभीर प्रभाव देखा गया है।

प्राकृतिक खेती न केवल मिट्टी की सेहत सुधारती है, बल्कि उत्पादन लागत भी कम करती है। आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में प्राकृतिक खेती के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इससे किसानों की आय बढ़ने और पर्यावरण संरक्षण दोनों में मदद मिल रही है।

गाँवों में ऊर्जा क्रांति- उनकी अपने किसानों से अपेक्षा यह भी है कि खेती में डीजल पंपों के स्थान पर सोलर पंपों का उपयोग होना चाहिए, इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा क्रांति लाना संभव है। डीजल महंगा होने के कारण किसानों की लागत बढ़ती है। वहीं सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दीर्घकालीन समाधान प्रदान करते हैं।यदि गाँव ऊर्जा आत्मनिर्भर बनते हैं, तब यह तय है कि भारत की आर्थिक संरचना और अधिक मजबूत होगी।

यहां कहना यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये पंद्रह सूत्र राष्ट्र निर्माण का जनआंदोलन हैं। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी उत्पादन, कृषि सुधार और सामाजिक जिम्मेदारी का व्यापक दृष्टिकोण शामिल है।भारत यदि इन सिद्धांतों को जीवनशैली का हिस्सा बना लेता है, तो आने वाले वर्षों में वह आर्थिक महाशक्ति तो बनेगा ही, साथ ही वह नैतिक और रणनीतिक रूप से भी विश्व का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बन सकता है।

सोने की खरीदारी में भी क्या कोई समझदारी है!

वक्रोक्ति

अंशु प्रधान
लेखक व्यंग्यकार हैं।

यूँ तो हमारा देश प्राचीन काल से लेकर मुगल काल तक सोने की चिड़िया कहलाता था मगर आजादी के बाद से ये चिड़िया गायब हुई तो ऐसी गायब हुई कि ढूंढना ही मुश्किल हो गया फिर बहुत ढूंढने पर मिली भी तो दो-तीन गुजराती व्यापारियों के ऊँचे महलों की अटारियों पर ,उनके महँगे जड़ाऊ सोने और हीरे, पन्ने के जेवरों पर ही नहीं बल्कि सोने और जवाहरातों से की गई ऊँचे क़िस्म की कारीगरी से सजाए गए महंगे और क़ीमती वस्त्रों पर ,भले ही वे वस्त्र रानियों के लिए नहीं बनवाये गए क्योंकि राजतन्त्र तो खत्म हो गया है न! मगर जिनके लिए भी बनवाये गए वे राजाओं से कम भी नहीं हैं जिनके हजारों हाथी काजू- बादाम और मेवे के लड्डू खाते हों वे लोग राजा से कम हो भी कैसे सकते हैं।

पता नहीं क्यों ये चिड़िया कुछ व्यापारियों,सेठों और नेताओं आदि की छतों पर ही जाने क्यों उड़कर बैठती है। कभी ही ऐसा हुआ हो जो कि किसी झोपड़ी पर आकर बैठी हो और अगर झोपड़ी पर बैठी भी होगी तो ज़रूर ही वो झोपड़ी घास-फूस की न होकर सोने की ही रही होगी। अरे भाई! झोपड़ी भी आजकल का नया ट्रेंड है आदमी कूल लगता है। ज़मीन से जुड़ा हुआ लगता है। लोगों को इसलिए बड़े बड़े महल नुमा घर बनाने के बाद उसी घर में मिट्टी घास फूस की आधुनिक टाइप झोपड़ी बनानी ही पड़ती है नहीं तो लोग घमंडी और अमीर समझेंगे।

वैसे भी हमारे देश की अधिकांश गरीब जनता जोकि दो वक़्त का खाना जुटाने की चिंता में ही जीवन गुजार देती है उसके लिए अब एक नई टेंशन और हो गयी अब मजदूर आदमी ये ही नहीं समझ पा रहा है कि साल भर तक सोना न खरीदने की अपील आखिर की किस से गयी। क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी तो सिर्फ गेहूं,आटा, बिजली का बिल, दूध का बिल, मकान का किराया, अस्पताल का खर्च आदि उठाने के लिए ही पैदा होकर मर- खप जाती है फिर ये सोना खरीद कौन रहा है।

भारत के लोग सारी जिंदगी इंगेजमेंट रिंग के अलावा दूसरी रिंग लेने की सोच तक नहीं पाते अगर रिंग लेनी भी पड़े तो वे अपनी बेटी- बेटे के लिए ही लेते हैं वो भी उनकी शादी के अवसर पर और जो लोग रोज़ जेवर बदलते हैं उन्हें फर्क क्या पड़ना तो फिर ये अपील है किसके लिए। जाहिर सी बात है उठते हुए मध्यमवर्ग के लिए बस यही वो वर्ग है जो सिर्फ कमर तुड़वाने के लिए और सभी का बोझा उठाने के लिए पैदा होता है।

हमारे देश में अभी सिर्फ सोना खरीदने के लिए मना किया गया है मैं उस दिन की फिक्र में हूँ जब कि कहा जायेगा कि आप लोग सप्ताह में तीन दिन का उपवास रखेंगे, हाय अच्छे दिन यही तो हैं! न खाना खाओ, न चर्बी बढ़े, न दिल की नसें ब्लॉक हों, न अस्पताल जाना पड़े,अहा! एक साथ कितने फायदे ही फायदे! हमारा देश कितने दूर की सोचता है।

मेरे ख्याल से इंसान अपनी शादी में ही सबसे ज्यादा सोना खरीदता है। अरे! तो शादी ही मत करो न! वैसे भी शादी करके किसने कौन सी कोई रियासत संभालनी होती है ज्यादातर तो घरों के बंटवारे ही होते हैं तो क्यों न एक पंथ दो काज करो,घर भी बच जाएगा और सोने का खर्चा भी..एक साथ कितनी बचत ही बचत, प्रीति भोज ये भोज वो भोज अंला- फलां सबका कंटक ही ख़त्म बस शान्ति ही शांति फिर आप आराम से नेता बन सकते हैं। अच्छा लीडर वही है जो सिर्फ खुद से प्यार करे, प्यार भी क्या बांटने की चीज़ है कोई! बस खुद के लिए जियो, खुद के लिए खुद पर ही मरो वो भी बार- बार, ये सोच कर कि मुझसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस यही सफल नेता होने की पहली सीढ़ी है।

रह गयी बात देश में और विदेश में घूमने-फिरने की और तेल की, तो तेल का क्या! गमले में उगा लेंगे। अरे! ये भारत की जनता है कुछ भी कर सकती है जब लोग भिंडी, प्याज ,ककड़ी आम, अमरुद तक गमले में उगा सकते हैं और खाली ढ़ोल बजा सकते हैं तो फिर क्या सरसों न उगा पाएंगे और फिर सरकार तो है ही आदमी का तेल निकालने के लिए और घूमने की तो सोचता ही कौन है! ये ऐसा देश है जहां घूमने का खर्चा जोड़कर आदमी उस पैसे की एफ डी बनाकर रखने की सोचता है कि चार पैसे होंगे तो वक़्त पर काम आएंगे। ये नदी,पहाड़,झरने तो वे मोबाइल में ही देख लेंगे कौन सी बड़ी बात है और घूम के हो ही क्या जाएगा, पैर दुखेंगे वो अलग! ऊपर से घर बंद पड़ा रहेगा। मान लो! बंद घर में चोर घुसे या कि कोई जानवर, किसने देखा? ऐसी सोच रखने वाली हमारे भारत देश की जनता सिर्फ शेखचिल्ली के हसीन सपने देखती है और सपनों में ही जी लेती है, हक़ीक़त में उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं बदलता और देश दुनिया की अपीलों से भी कुछ नहीं बदलता।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पब्लिक बोली सिंहासन छोड़ो, अब खेला हम करीबो

गाँव की चौपाल से लेकर शहर की चाय की दुकानों तक, हर जगह एक ही चर्चा है, क्या सोच कर वोट दिया था, और हो क्या गया। यही लोकतंत्र का सबसे रोचक और रहस्यमय पक्ष है। चुनाव से पहले जनता बड़े-बड़े सपने बुनती है। सड़कें चमकेंगी, रोजगार की बारिश होगी, महँगाई गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मतदान संपन्न होता है, एक अजीब-सी शांति छा जाती है, मानो जनता खुद ही कह रही हो। अब पाँच साल की छुट्टी। इस बार का चुनावी मिजाज कुछ ऐसा रहा जैसे बरसात का मौसम, कभी तेज धूप, कभी घने बादल, तो कभी मूसलाधार बारिश। नेता लोग पूरी कोशिश में लगे रहे कि हवा का रुख समझ लें, लेकिन असली हवा तो जनता के मन में बहती है। और यह मन कब करवट ले ले, इसका पूर्वानुमान किसी मौसम विभाग के पास भी नहीं।

व्यंग्य

प्रभुनाथ शुक्ल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आते ही देश की जनता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि असली सत्ता उसी के हाथ में है। लोकतंत्र की असली मदारी वहीं है। बाद में वह खुद तमाशा बन जाय यह दीगर बात है। उससे भी बड़ी बात यह कि उसका मूड किसी मौसम से कम नहीं। कब बदल जाए, किस दिशा में मुड़ जाए, इसका अनुमान लगाना तो दूर, खुद जनता को भी पहले से नहीं पता होता।

गाँव की चौपाल से लेकर शहर की चाय की दुकानों तक, हर जगह एक ही चर्चा है, क्या सोच कर वोट दिया था, और हो क्या गया। यही लोकतंत्र का सबसे रोचक और रहस्यमय पक्ष है। चुनाव से पहले जनता बड़े-बड़े सपने बुनती है। सड़कें चमकेंगी, रोजगार की बारिश होगी, महँगाई गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मतदान संपन्न होता है, एक अजीब-सी शांति छा जाती है, मानो जनता खुद ही कह रही हो। अब पाँच साल की छुट्टी।

इस बार का चुनावी मिजाज कुछ ऐसा रहा जैसे बरसात का मौसम, कभी तेज धूप, कभी घने बादल, तो कभी मूसलाधार बारिश। नेता लोग पूरी कोशिश में लगे रहे कि हवा का रुख समझ लें, लेकिन असली हवा तो जनता के मन में बहती है। और यह मन कब करवट ले ले, इसका पूर्वानुमान किसी मौसम विभाग के पास भी नहीं।

लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। यहाँ राजा कोई जन्म से नहीं होता, जनता उसे बनाती है। और वही जनता, जब मन भर जाता है, तो बड़े आराम से कह देती है अब बहुत हुआ, नीचे उतरिए। मतदान केंद्र पर उँगली पर स्याही लगते ही हर नागरिक के भीतर एक अदृश्य सत्ता जाग उठती है। वह खुद को देश का निर्णायक मानने लगता है। वोट डालकर बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े निर्णयकर्ता से कम नहीं होता।

राजनीति भी कम दिलचस्प खेल नहीं है। चुनाव के समय हर गली-नुक्कड़ पर मीठी बातें, वादों की मिठाई और भविष्य के रंगीन सपनों की सजावट होती है। हर भाषण में उम्मीद की नई इमारत खड़ी की जाती है। लेकिन जैसे ही परिणाम आते हैं, जनता के मन में एक पुरानी घंटी बज उठती है, यह सब तो पहले भी सुना था!

धीरे-धीरे जनता भी परिपक्व हो रही है। अब वह सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं होती। अब वह सवाल पूछती है–क्या बदला? कैसे बदला? हमारे जीवन में क्या फर्क आया? यह प्रश्न अब आम बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। यह बदलाव लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि जागरूक जनता ही असली ताकत होती है।

लेकिन व्यंग्य का सबसे रोचक पहलू यह है कि जनता खुद भी कभी-कभी भूल जाती है। आज जिस पर नाराज होती है, कल उसी से फिर उम्मीदें बाँध लेती है। राजनीति का यह चक्र ऐसा है जिसमें हर पाँच साल में नए चेहरे, नए संवाद और नई परिस्थितियाँ सामने आती हैं, लेकिन कहानी का मूल ढाँचा लगभग वही रहता है।

लोकतंत्र दरअसल एक विशाल रंगमंच है। इसमें जनता निर्देशक है, नेता अभिनेता हैं और चुनाव सबसे बड़ा मंचन। दिलचस्प बात यह है कि दर्शक भी वही जनता है, जो कभी ताली बजाती है, कभी हूटिंग करती है और कभी पूरी पटकथा ही बदल देती है।

अब सबकी नजर अगले शो पर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगली बार जनता कौन-सा नया मोड़ लेकर आती है। क्योंकि इस पूरे खेल का एक ही अटूट नियम है जनता का मन। और सच यही है कि इस मन को समझ पाना शायद भगवान के लिए भी आसान नहीं।

हमारी दुनिया

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

डिंका जनजाति: गायों में निहित हैं उनके सुख-दुख

सूरज ढलने लगा था और आसमान में लाल, नारंगी और बैंगनी रंग की छटा बिखरने लगी थी। तभी, अचानक एक आवाज़ गूंजी। यह आवाज़, गाय के सींग से बनाए गए एक वाद्य यंत्र की थी। यह आवाज़, गायों के लिए वापस लौटने का संकेत थी। जैसे ही यह आवाज़ सुनाई दी, सैंकड़ों गायें, जंगल से लौटकर मैदान में आने लगीं। ये गायें, डिका जनजाति के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। वे उन्हें दूध, मांस और चमड़ा प्रदान करती थीं। इसके अलावा, वे उनकी धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक थीं। गायों के सींग, बहुत ही अनोखे और विशाल थे। कुछ सींग, इतने बड़े थे कि वे गायों के सिर से भी ऊँचे थे। ये सींग, गायों को एक भव्य और डरावना रूप प्रदान कर रहे थे। ?गायें, बिना किसी हिचकिचाहट के, सीधे अपने निर्धारित खूंटों पर पहुँच गईं। यह देखकर, ऐसा लग रहा था कि वे अपने खूंटों को पहले से ही जानती थीं। डिका जनजाति के लोग, गायों को बांधने के लिए आगे बढ़े। जैसे-जैसे शाम गहराती गई, अलावों से उठता हुआ धुआँ और भी घना होता गया। यह धुआँ, गायों के सींगों और लोगों के चेहरों पर एक रहस्यमयी आभा फैला रहा था। यह दृश्य, किसी ज्योग्राफिकल चैनल की फिल्म की तरह लग रहा था। यह अनोखा सुंदर दृश्य दक्षिण सूडान की यात्रा करते यूट्यूबर और विश्व यात्री दावूद अखुंदजादा अपने कैमरे से हम तक पहुंचाते हैं तो जैसे हम दर्शक भी उसका हिस्सा बन जाते हैं।

सुबह की सुनहरी लालिमा अभी छंटी भी नहीं थी कि दक्षिण सूडान की डिका जनजाति की बस्ती में हलचल शुरू हो गई। यह बस्ती, खुले मैदान में फैली हुई थी और चारों तरफ से ऊँचे-ऊँचे घास के मैदानों और पेड़ों से घिरी हुई थी। मैदान के बीचोबीच, जहाँ तक नज़र जाती थी, वहाँ सैंकड़ों गायों को बांधने के लिए खूंटे गड़े हुए थे। अलावों से उठता हुआ धुआँ, हवा में मिलकर एक अनोखी गंध फैला रहा था। यह गंध, गोबर के जलने की गंध थी, जो डिका जनजाति के लोगों के लिए पवित्र थी। वे मानते थे कि यह धुआँ, उन्हें बुरी आत्माओं से बचाता है। खूंटों के पास ही, लोगों ने अपने सोने-बैठने के लिए लकड़ी के ढांचे बना रखे थे। ये ढांचे, खटियाओं की तरह दिखते थे और उन पर चमड़े या कपड़े बिछाए हुए थे। कुछ लोग, इन ढाँचों पर बैठे हुए थे, जबकि कुछ लोग, आग के पास बैठकर गपशप कर रहे थे।

सूरज ढलने लगा था और आसमान में लाल, नारंगी और बैंगनी रंग की छटा बिखरने लगी थी। तभी, अचानक एक आवाज़ गूंजी। यह आवाज़, गाय के सींग से बनाए गए एक वाद्य यंत्र की थी। यह आवाज़, गायों के लिए वापस लौटने का संकेत थी। जैसे ही यह आवाज़ सुनाई दी, सैंकड़ों गायें, जंगल से लौटकर मैदान में आने लगीं। ये गायें, डिका जनजाति के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। वे उन्हें दूध, मांस और चमड़ा प्रदान करती थीं। इसके अलावा, वे उनकी धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक थीं। गायों के सींग, बहुत ही अनोखे और विशाल थे। कुछ सींग, इतने बड़े थे कि वे गायों के सिर से भी ऊँचे थे। ये सींग, गायों को एक भव्य और डरावना रूप प्रदान कर रहे थे।

गायें, बिना किसी हिचकिचाहट के, सीधे अपने निर्धारित खूंटों पर पहुँच गईं। यह देखकर, ऐसा लग रहा था कि वे अपने खूंटों को पहले से ही जानती थीं। डिका जनजाति के लोग, गायों को बांधने के लिए आगे बढ़े। जैसे-जैसे शाम गहराती गई, अलावों से उठता हुआ धुआँ और भी घना होता गया। यह धुआँ, गायों के सींगों और लोगों के चेहरों पर एक रहस्यमयी आभा फैला रहा था। यह दृश्य, किसी ज्योग्राफिकल चैनल की फिल्म की तरह लग रहा था। यह अनोखा सुंदर दृश्य दक्षिण सूडान की यात्रा करते यूट्यूबर और विश्व यात्री दावूद अखुंदजादा अपने कैमरे से हम तक पहुंचाते हैं तो जैसे हम दर्शक भी उसका हिस्सा बन जाते हैं।

दरअसल डिंका जनजाति की बस्ती, एक ऐसी जगह है जहाँ परंपरा और आधुनिकता, एक साथ मौजूद होती हैं। यहाँ के लोग, अपनी संस्कृति और परंपराओं को बहुत महत्व देते रहे हैं। वे अपनी गायों से प्यार करते हैं और उनके साथ एक गहरा रिश्ता रखते रहे हैं।

दक्षिण सूडान की डिंका जनजाति के लिए गाय सिर्फ जानवर नहीं, धन, धर्म, पहचान और जिंदगी, सबकुछ है। इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी पशुपालक जनजातियों में गिना जाता है। डिंका के पास खेती कम है। गाय ही इनकी बचत, बीमा और निवेश है। परिवार कितना अमीर है ये गायों की संख्या से तय होता है। चीजें खरीदने-

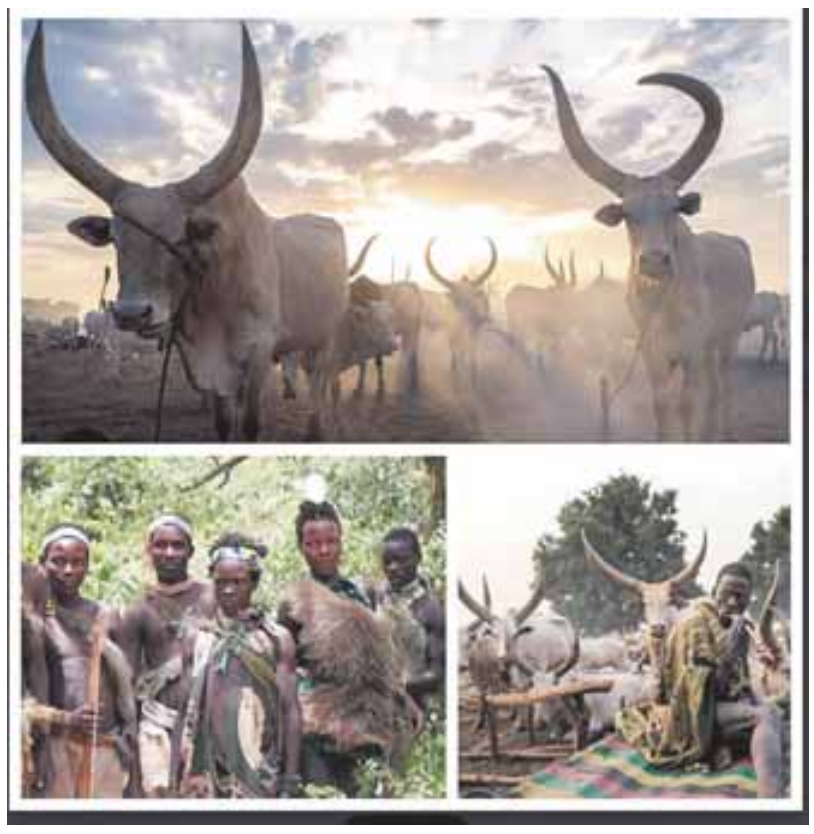

बेचने के लिए भी गायें दी जाती हैं। बीमारी, सूखा या युद्ध में गायें बेचकर ही गुजारा होता है।

शादी और रिश्ते गायों पर टिके हैं, लड़के को शादी के लिए लड़की के परिवार को 20 से 200 गायें तक देनी पड़ती हैं। गाय जितनी ज्यादा, दुल्हन का परिवार उतना खुश। शादी के बाद दोनों परिवार गायों के लेन-देन से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। तलाक हुआ तो गायें वापस करनी पड़ती हैं। यह भी मजेदार है कि जिसके पास ज्यादा गायें होंगी उसकी बेटी की शादी बड़े घर में होगी। कम गाय वाला लड़का अक्सर अविवाहित रह जाता है।

धर्म और पहचान में यहां गाय एक पवित्र पशु है। डिंका एनिमिस्ट और ईसाई परंपराओं को मिलाकर चलते हैं। गाय को न्हियालिक नाम के ईश्वर का उपहार माना जाता है। डिंका पुरुष अक्सर अपना नाम अपनी पसंदीदा गाय के रंग-रूप पर रखते हैं। जैसे 'मचार' मतलब सफेद बैल वाला। युवा चरवाहे अपनी गायों के लिए गीत लिखते हैं, उनकी तारीफ में नाचते हैं। ये 'ऑक्स-सॉन्ग' उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है। डिंका के लिए सींग का तुरही सिर्फ म्यूजिक नहीं, वॉकी-टॉकी, अलार्म और पहचान तीनों है। गाय उनकी जिंदगी है, तो गाय का सींग उनकी आवाज बन जाता है।

जनजाति में 8-10 साल की उम्र से ही लड़के पशु बाड़ा (कैटल कैंप) में रहने लगते हैं। पूरा दिन गाय चराना, उनकी रक्षा करना, दूध निकालना इनकी दिनचर्या होती है। दूध मुख्य भोजन है। गाय का मूत्र सिर धोने और राख से दांत साफ करने में इस्तेमाल होता है। गोबर से घर लीपते हैं और मच्छर भगाने के लिए जलाते हैं। बछड़ों के सींग को गर्म लोहे से मनचाहा आकार दिया जाता है। टेढ़े-मेढ़े सींग सुंदरता और मालिक की शान माने जाते हैं।

यहां गायों की अहमियत इतनी है कि इन्हें पाने के लिए मवेशी छापे आम हैं। खासकर नुएर और मुर्ले जनजाति से लड़ाइयां होती रहती हैं। दशकों के गृहयुद्ध से एके 47 जैसी बंदूकें हर चरवाहे के पास आ गई हैं, जिससे संघर्ष और अधिक खूनी हो गया है।वस्तुतः डिंका लोगों के लिए गाय खोना मतलब सबकुछ खोना है। शादी नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी, भगवान नाराज होगा। इसलिए वो गाय के लिए जीते हैं और मरते भी हैं।

दक्षिण सूडान की उन जनजातियों (जैसे मुंडारी या डिंका) का जीवन वास्तव में किसी महाकाव्य जैसा प्रतीत होता है। धूल, धुआं और उन विशाल सींगों वाली अंकोले-वातुसी गायों के बीच का वह सामंजस्य प्रकृति और मनुष्य के प्राचीन जुड़ाव की याद दिलाता है।

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया पेंशनरों के हित में फैसला

छत्तीसगढ़ पेंशनर संघ के प्रान्ताध्यक्ष श्री चेतन भारती ने 12 अगस्त 2021 को अपने अधिवक्ता श्री क्षितिज शर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दोनों राज्यों के पेंशनरों के साथ हो रहे अन्याय के विरूद्ध न्याय प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उसी याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को राज्य सरकारों द्वारा छठवें वेतनमान का 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक 32 माह का एरियर नहीं दिया गया था। इसी प्रकार सातवें वेतनमान में भी 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक 27 माह की एरियर राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के अनुसार दोनों राज्यों को छठवें वेतनमान का 32 माह का एरियर और सातवें वेतनमान की 27 माह की एरियर राशि का 120 दिनों में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के भुगतान करने के आदेश दिए है।

छत्तीसगढ़ पेंशनर संघ के प्रान्ताध्यक्ष श्री चेतन भारती ने 12 अगस्त 2021 को अपने अधिवक्ता श्री क्षितिज शर्मा के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दोनों राज्यों के पेंशनरों के साथ हो रहे अन्याय के विरूद्ध न्याय प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उसी याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को राज्य सरकारों द्वारा छठवें वेतनमान का 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक 32 माह का एरियर नहीं दिया गया था। इसी प्रकार सातवें वेतनमान में भी 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक 27 माह की एरियर राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर दोनों राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे अन्याय के कारण दुखी और परेशान थे। खास बात यह है कि दोनों राज्य सरकारों द्वारा नियमित कर्मचारियों को छठवें और सातवें वेतनमान की एरियर की राशि का भुगतान कर दिया गया। किंतु पेंशनरों के साथ दोनों राज्य सराकरों द्वारा भेदभाव करते हुए छठवें और सातवें वेतनमान की एरियर राशि नहीं दी गई।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर संगठन द्वारा दोनों राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार मिलकर और ज्ञापन देकर एरियर राशि देने का अनुरोध कर रहे थे। किंतु दोनों राज्य सरकारों ने पेंशनरों की अभी तक नहीं सुनी। पेंशनर संगठनों द्वारा छठवें और सातवें वेतनमान की एरियर राशि के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। किन्तु उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस कारण मजबूर होकर पेशनर संगठन ने उच्च न्यायालय की शरण ली और उच्च न्यायालय द्वारा पेंशनरों के हित में निर्णय लिया गया।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 120 दिनों में छठवें और सातवें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान करें। अब अन्याय बहुत हो चुका। पेंशनरों के हित में उच्च न्यायालय का जो निर्देश आया है, उसके लिए दोनों राज्यों के पेंशनर संगठनों को एकजुट होकर एरियर राशि प्राप्त करने की आवश्यकता है।

पिछले दिनों 10 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भी महँगाई भत्ते और महँगाई राहत पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकारें कर्मचारियों और पेंशनधारियों में भेदभाव नहीं कर सकती। क्योंकि महंगाई का असर दोनों पर समान रूप से पड़ता है। इसलिए राज्य सरकारों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देते समय भेदभाव नहीं करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी.वराले की पीठ ने पिछले दिनों केरलम सरकार और केरलम राज्य सड़क परिवहन निगम की अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें पेंशनधारियों को अलग दर से मंहगाई राहत देने का फैसला सही ठहराया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को भी समानता का अधिकार है। इसलिए उन्हें किसी भी तरह से कमतर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा के पेंशनर केवल पेंशन के ही नहीं, बल्कि महंगाई राहत के भी हकदार है, जो समय-समय पर महंगाई के आधार पर बढ़ाई जाती है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर देशभर के लाखों पेंशनधारियों पर पड़ सकता है। अब राज्य सरकारें और सरकारी संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे महंगाई राहत तय करते समय सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करें। यह फैसला पेंशधारियों के अधिकारों को मजबूत करता है। और ये संदेश भी देता है कि कर्मचारियों के रिटायर्ड होने के बाद भी पेंशनरों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आर्थिक नीतियों में भी समानता का सिद्धांत लागू होगा और किसी भी तरह की मनमानी को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पेंशनरों को पेंशन राहत देते समय एक बड़ा अड़ंगा मध्यप्रदेश राज्य गठन अधिनियम की धारा 49 (6) का बहाना लेकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पिछले अनेक सालों से भेदभाव किया जा रहा है। उक्त धारा का बहाना लेकर राज्य सरकार सेवारत कर्मचारियों को तो महंगाई भत्ता देने का आदेश उसी तारीख से देते है, जिस तारीख से केन्द्र ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है। किन्तु पेंशनरों को उसी समय महंगाई राहत स्वीकार नहीं करते हुए धारा 49 (6) का बहाना करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार का नाटक करती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार भी पेंशनरों के साथ भेदभाव करते हुउ उस तारीख से पेंशन नहीं देती है, जिस तारीख से केन्द्र सरकार मंहगाई भत्ता, महंगाई राहत की घोषणा करता है। देर से महंगाई राहत की सहमति प्राप्त होने के कारण मध्यप्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई तारीख से महंगाई राहत की घोषणा करती है, जिसमें कई महीनों की देरी हो जाती है और पेंशनरों को एरियर की राशि भी नहीं दी जाती। इस कारण वर्षों से पेंशनरों के साथ भेदभाव होता आ रहा है। समस्या की जड़ धारा 49 (6) को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री उक्त धारा को समाप्त करने का निर्णय लेकर केन्द्र सरकार को भेजे। इस धारा के समाप्त करने के बाद ही पेंशनरों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म होगा।

उच्च न्यायालय बिलासपुर और सुप्रीम कोर्ट के उक्त दोनों फैसलों का आदर और सम्मान करते हुए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्रियों को पेंशनरों के हित में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। आशा है दोनों राज्य के मुख्यमंत्री अपनी संवेदनशीलता का परिचय देंगे और पेंशनरों के हित में सही निर्णय लेंगे।

पुस्तक समीक्षा

दीपक गिरकर

समीक्षक

संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ की सूक्ष्म, किंतु सशक्त अभिव्यक्ति

हिंदी साहित्य के आकाश में सतीश राठी की सृजनधर्मिता एक दीप्त नक्षत्र की भाँति आलोकित है। सतीश राठी की संवेदनशील, सजग और सशक्त लेखनी ने न केवल एक विशिष्ट पहचान अर्जित की है, अपितु समकालीन साहित्य को गहन अर्थवत्ता भी प्रदान की है। इनकी रचनाएँ समय की धड़कनों को सुनती हैं, समाज की विसंगतियों को पहचानती हैं और मानवीय मूल्यों की ऊष्मा को अत्यंत मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त करती हैं। विशेषतः लघुकथा विधा को सतीश राठी ने जिस साधना, सूक्ष्म दृष्टि और शिल्प-संपन्नता के साथ साधा है, वह हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनकी लघुकथाएँ केवल कथ्य नहीं, बल्कि समय-साक्षी दस्तावेज़ बनकर पाठकों के अंतर्मन को स्पर्श करती हैं। इनकी रचनाएँ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर नई पीढ़ी को संवेदनशील दृष्टि दे रही हैं और विभिन्न भाषाओं में अनूदित होकर व्यापक पाठक-समाज तक पहुँच रही हैं। क्षितिज साहित्यिक संस्था के माध्यम से सतीश राठी का मार्गदर्शन अनेक नवांकुर रचनाकारों के लिए प्रेरणास्त्रोत रहा है। इन्होंने युवा लेखकों को केवल प्रोत्साहन ही नहीं दिया, बल्कि उनकी सृजनात्मक चेतना को दिशा और संस्कार भी प्रदान किए। इंदौर से लघुकथा के क्षेत्र में उभरती सशक्त उपस्थिति सतीश राठी की साहित्य-सेवा का उज्ज्वल परिणाम है।

सतीश राठी का साहित्यिक स्थान आज भारतीय लघुकथा-जगत में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित माना जाता है। यह प्रतिष्ठा उन्हें केवल रचनाओं की संख्या के कारण नहीं, बल्कि उनकी वैचारिक गहराई, सामाजिक प्रतिबद्धता और अभिव्यक्ति की सादगी के कारण प्राप्त हुई है। वे उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने लघुकथा को न तो हल्की विधा समझा और न ही उसे मात्र मनोरंजन का माध्यम बनाया, बल्कि उसे समाज-परिवर्तन की सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का गंभीर प्रयास किया। सतीश राठी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषा है। वे अत्यंत सरल, सहज और संप्रेषणीय शब्दावली का प्रयोग करते हैं, किंतु उस सरलता में विचारों की गहनता और संवेदनाओं की तीव्रता समाहित रहती है। उनकी रचनाएँ पढ़ते समय पाठक को भाषा की जटिलता से जूझना नहीं पड़ता, बल्कि वह सीधे कथ्य के मर्म तक पहुँच जाता है। यही कारण है कि उनकी लघुकथाएँ व्यापक पाठक-वर्ग तक सहजता से पहुँचती हैं और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती हैं।

सतीश राठी का पहला लघुकथा संग्रह 'शब्द साक्षी हैं' वर्ष 2002 में सत्य प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होकर आया था। यह संग्रह काफी चर्चित रहा था। इस लघुकथा संग्रह की भूमिका डॉ. सतीश दुबे ने लिखी थी। डॉ. सतीश दुबे ने अपनी भूमिका में लिखा था 'लेखकीय उद्देश्य की तमाम शर्तों के बहुत नजदीक होने के कारण सतीश राठी का नाम श्रेष्ठ लघुकथाकारों के बीच स्वतः दर्ज हो जाता है। लघुकथा के गुणात्मक एवं मात्रात्मक लेखन के साथ विधा के विकास हेतु किये गए प्रयासों की चर्चा जब कभी होगी, तब सतीश राठी नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा, यह तय है।' इस संग्रह में छोटी-बड़ी 80 लघुकथाएँ हैं।

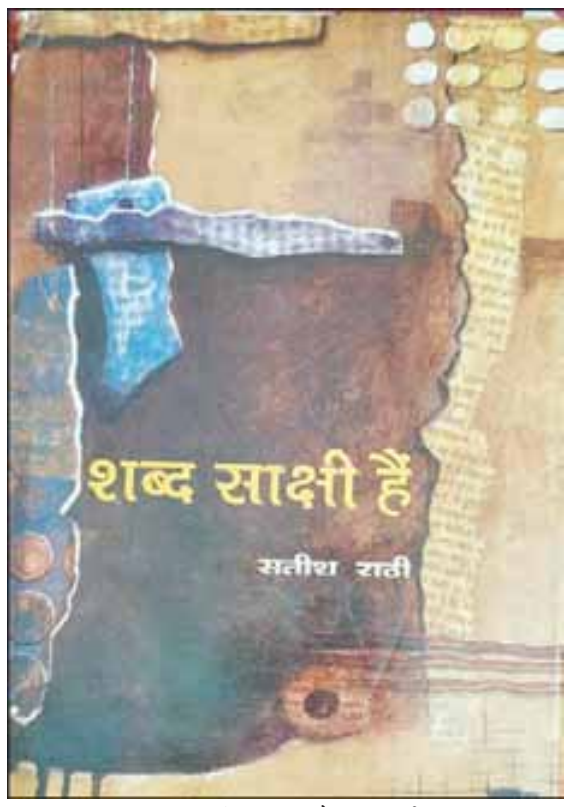

'दाँये-बाँये' लघुकथा अत्यंत संक्षेप में प्रभावी व्यंग्य प्रस्तुत करती है। इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच सत्ता-संरक्षण की विडंबना को चतुराई से उजागर किया गया है। साधारण संवाद के माध्यम से सामाजिक असमानता पर तीखा कटाक्ष किया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी सफलता है। 'भिखमंगे' लघुकथा बहुत कम शब्दों में एक गहरी विडंबना प्रस्तुत करती है। इसमें दान देने की प्रक्रिया और उससे उपजी अव्यवस्था को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है, जहाँ सहायता का प्रयास ही हिंसक छीना-झपटी में बदल जाता है। अंत में दानकर्ता स्वयं भिखमंगा जैसा दिखने लगता है, जो सामाजिक असमानता और मानवीय विफलता पर तीखा व्यंग्य है। 'मिलावट' लघुकथा मिलावट और नैतिक पतन पर तीखा व्यंग्य प्रस्तुत करती है। सेठ स्वयं हर वस्तु में मिलावट करवाता है, लेकिन चाय में मिलावट का अनुभव होते ही उसका आक्रोश सामने आ जाता है। अंत में रामू की मुस्कुराहट इस दोहरे चरित्र, दूसरों के साथ छल करने और अपने साथ होते ही उसे अस्वीकार करने को प्रभावी ढंग से उजागर करती है। 'सूअर' लघुकथा अत्यंत प्रभावशाली ढंग से मानवीय संवेदनहीनता और विरोधाभास को उजागर करती है। भूखे बच्चे को भोजन देने से इनकार और उसी समय घर की झूठन को कचरे में डाल देना, समाज में व्याप्त असमान संवेदना और असंगत मूल्य-व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। अंत का प्रतीकात्मक 'सूअर' दृश्य इस विडंबना को और अधिक कठोर बना देता है।

सतीश राठी की लघुकथाएँ समकालीन हिंदी साहित्य में मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ की सूक्ष्म, किंतु सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी रचनाओं का आधार मानव-मन की वे गहन अनुभूतियाँ हैं, जो प्रायः अदृश्य रहकर भी जीवन की आंतरिक धारा को संचालित करती हैं। सरल, सहज और अलंकरण-विहीन भाषा में रचित ये लघुकथाएँ कथ्य की तीव्रता और भाव-सघनता के कारण गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। प्रत्येक कथा पाठक को केवल घटनाओं से परिचित नहीं कराती, बल्कि उसे आत्ममंथन और सामाजिक यथार्थ के पुनर्पाठ के लिए प्रेरित करती है। इन रचनाओं में पारिवारिक संबंधों की ऊष्मा, नैतिक द्वंद्व, मूल्य-विचलन, करुणा और विडंबना का मार्मिक चित्रण मिलता है। लेखक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानवीय व्यवहार की जटिलताओं को उकेरते हैं, जिससे पाठक सहज ही कथा के भीतर प्रवेश कर स्वयं को उससे संबद्ध अनुभव करता है। सतीश राठी की दृष्टि यथार्थवादी होते हुए भी आशा से विमुख नहीं है; वे सामाजिक विसंगतियों के बीच सुधार और संवेदना की संभावना को निरंतर उजागर करते हैं। उनकी लघुकथाएँ व्यंग्य, करुणा और मौन प्रतिरोध के माध्यम से समय की विसंगतियों पर प्रभावी प्रहार करती हैं। समग्रतः, यह 'शब्द साक्षी हैं' संग्रह कथ्य, भाषा और संवेदना के संतुलन से युक्त होकर समकालीन हिंदी लघुकथा-साहित्य में एक उल्लेखनीय और स्थायी योगदान के रूप में स्थापित होता है।

पुस्तकः शब्द साक्षी हैं (लघुकथा संग्रह)
लेखक : सतीश राठी
प्रकाशक : सत्य प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य : 120/- रूपए

सांसद सावित्री ठाकुर के प्रयासों से धार -महू लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा और आधारभूत विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली

142 करोड़ 65 लाख रुपए की बड़ी सौगात से लोकसभा क्षेत्र के 36 हाईस्कूलों में होंगे निर्माण एवं विकास कार्य, जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं

धार। धार महू लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा और आधारभूत विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के सतत प्रयासों से लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में विकास कार्यों हेतु 142 करोड़ 65 लाख 36 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राशि मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा जारी की गई है।

लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत राशि के अंतर्गत धार विधानसभा के 7, गंधवानी विधानसभा के 6, सरदारपुर विधानसभा के 6, कुक्षी विधानसभा के 9 तथा मनावर विधानसभा के 8 हाई स्कूलों में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य किए जाएंगे। इन विद्यालयों में भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, छात्र-छात्राओं हेतु आवश्यक सुविधाएं तथा अन्य आधारभूत विकास कार्य संपादित किए जाएंगे, जिससे आदिवासी अंचल के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा।

सांसद सावित्री ठाकुर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री की सोच है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे और शिक्षा के माध्यम से हर वर्ग को सशक्त बनाया जाए। इसी संकल्प के साथ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

सावित्री ठाकुर ने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास, शिक्षा के विस्तार तथा ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं।

आदिवासी अंचल में शिक्षा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे- श्रीमती सावित्री ठाकुर ने जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह के प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके सहयोग एवं सकारात्मक पहल से लोकसभा क्षेत्र को यह बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर वातावरण मिलेगा तथा आदिवासी अंचल में शिक्षा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

सोहागपुर में 82 अधिवक्ताओं ने मताधिकार दिए

सोहागपुर। राज्य अधिवक्ता परिषद के तत्वावधान में 12 मई को मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न कराए गए। इस अवसर पर सोहागपुर न्यायालय में सोहागपुर व माखन नगर के अधिवक्ताओं ने स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के लिए वोट डाले हैं।सह सचिव शिव कुमार पटेल ने बताया इस चुनाव में पूरे प्रदेश से 122 अधिवक्ताओं ने सदस्य के लिए चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं। इस चुनाव में एक अधिवक्ता 1 से लेकर 25 तक के क्रम से अलग अलग अधिवक्ताओं के लिए वोट डाल सकता है। सोहागपुर में 104 अधिवक्ता रजिस्टर्ड है। जिसमें से 82 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। उल्लेखनीय है कि भले ही अधिवक्ता एक दूसरे के विरुद्ध पैरवी करते हैं। लेकिन सोहागपुर के अधिवक्ता संघ के चुनाव अनुकरणीय होने का इतिहास साक्षी है। यहां करीबन सौ सालों से अधिक समय से निरंतर अध्यक्ष एवं पदाधिकारी।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल एवं वर्चुअल माध्यम से पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संभाग प्रभारियों व प्रदेश प्रशिक्षण टोली की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर संभाग प्रभारी एवं टोली के सदस्य उपस्थित रहे।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर जनसमस्याओं का किया त्वरित समाधान

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया। जिन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जा सका, उन्हें संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी कठिनाइयों को समझा और उन्हें जल्द से जल्द समाधान दिलाने का आश्वासन दिया।

तौल की रफ्तार धीमी, किसान परेशान, करना पड़ रहा लंबा इंतजार

केन्द्रों पर धूप से बचने किसानों को लेना पड़ रहा ट्रेक्टर-ट्रॉलियों का सहारा

एस. के. द्विवेदी, बैतूल। मध्यप्रदेश का बैतूल जिला हर साल बड़े पैमाने पर गेहूं के उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो प्रदेश एवं देश की खाद्य सुरक्षा में विशेष योगदान करता है लेकिन इस बार गेहूं तुलाई के मामलों में सरकारी नीतियों और प्रक्रियाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर गेहूं तुलाई के लिए प्रक्रिया जटिल और समय बाध्य होने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे है। किसानों की स्लॉट बुकिंग की समस्या सुलझाने के बाद अब खरीदी केंद्रों पर तुलाई की धीमी रफ्तार ने उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हालात यह है कि इस भीषण गर्मी के बीच जब लोग कूलर और पंखों के सामने से हटने को तैयार नहीं, तब अन्नदाता खुले आसमान और तपती धूप के नीचे दिन-रात गुजारने को मजबूर हैं। भीषण धूप से बचने के लिए किसानों के पास केवल सडक़ का बिछौना और ट्रैक्टर-ट्राली की छांव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में समर्थन मूल्य में गेहूं का उपार्जन किसानों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। टिगरिया गांव के किसान चंद्रशेखर यादव, बैतूलबाजार के प्रसून चौधरी, बंटी वर्मा आदि का कहना है कि पहले खरीदी शुरू करने में देरी हुई। फिर सैटेलाइट सर्वे, स्लॉट बुकिंग में दिक्कतें और अब केंद्रों पर खरीदी की धीमी रफ्तार ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों का आरोप है कि कई खरीदी केन्द्रों पर चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त सुविधा तक नहीं है। किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली या पेड़ों के नीचे छांव में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे है। एक-दो दिन से लेकर तीन दिन के लंबे इंतजार के बाद भी तुलाई नहीं हो पा रही है। केन्द्रों पर दोपहर 12 बजे के बाद खरीदी शुरू होती है। दिनभर में 5-6 ट्रॉलियां ही मुश्किल तौली जाती है। ऊपर से हर दिन बिगड़ते मौसम के कारण किसानों को फसल भीगने की चिंता अलग से सता रही है। जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष गब्बर गोचरे का कहना है कि केंद्रों पर खरीदी की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि किसानों को लंबे समय तक तौल का इंतजार न करना पड़े। उनका कहना है कि किसान की परेशानियों का समाधान तभी संभव है, जब सरकार, प्रशासन अपनी नीतियों को जमीनी हकीकत के अनुरूप बनाकर उन्हें धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू करें।

18,969 किसानों का पंजीयन, 8965 किसानों ने बेचा गेहूं- जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए बड़ी संख्या में किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। गेहूं बेचने के लिए जिले में 18969 किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं 8965 किसानों से लगभग 48,772 मेट्रिक टन (लगभग 4,84,724 क्विंटल) गेहूं की खरीदी की गई है। बताया जा रहा है कि जिले में अभी भी 1-2 खरीदी केन्द्र ऐसे है, जहां अभी तक खरीदी शुरू नहीं हुई है। हालांकि इन केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसानों ने स्लॉट जरूर बुक कराया है, लेकिन अभी तक उपज लेकर केन्द्र नहीं पहुंचे है, जिससे इन केंद्रों पर खरीदी का आंकड़ा शून्य है। वैसे अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इन केंद्रों पर भी किसान पहुंचने लगेगे।

केन्द्र बस्ती से दूर, चाय-पानी तक को तरस रहे किसान- जिले में गेहूं खरीदी के लिए 64 केन्द्र बनाये गये है। इनमें से कुछ केन्द्र गांव-बस्ती से दूर वेयर हाउस में बने है। जो रिहायशी इलाको से काफी दूर सुनसान स्थानों पर स्थित है। केन्द्र पर केवल पीने के पानी की व्यवस्था है, लेकिन चाय-नाश्ते की काफी परेशानी है। ऐसे में किसानों को यदि चाय भी पीना है तो काफी दूर तक जाना पड़ता है। किसानों ने बताया कि अधिकारियों द्वारा बार-बार निरीक्षण कर केन्द्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त छांव और पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये है, लेकिन यह निर्देश केवल अधिकारियों के मौखिक आदेश तक ही सीमित है। यह निर्देश धरातल पर अभी तक लागू नहीं हो सके हैं। केन्द्रों पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

किसानों को 80 करोड़ का भुगतान

इस साल शासन द्वारा 2625 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया गया है। इसमें गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये है, जबकि 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा सरकार ने की है। जिसकी वजह से इस साल जिले के अधिकतर किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की उपज बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इन किसानों को अब तक लगभग 80 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 15 करोड़ के भुगतान पर हस्ताक्षर होकर यह पाइप लाइन में है। अब तक जिले में 8965 किसानों से लगभग 48,772 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। जिला खाद्य अधिकारी कृष्ण कुमार टेकाम का कहना है कि जैसे-जैसे गेहूं की खरीदी हो रही है, किसानों का भुगतान भी किया जा रहा है। यदि किसी किसान की स्लॉट बुकिंग की आज अंतिम तारीख है, तो उसे तौल पर्ची जारी कर दे रहे हैं, इसके बाद अगले 2 दिन में समिति वाले बिल जनरेट कर देते हैं, और भुगतान कर दिया जाता है।

50 प्रतिशत चमक विहीन गेहूं भी खरीद रही सरकार- बेमौसम बारिश की मार झेल चुके किसानों के लिए राहत भरी खबर यह है कि असमय वर्षा के कारण गेहूं की फसल की चमक कम हो गई है। चमकविहीन गेहूं की खरीदी पर नियमों में ढील देकर किसानों को राहत दी गई है। लस्टर लॉस का मानक 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा टूटे और सिकुड़े हुए दानों के मानक में भी ढील दी गई है। बताया जा रहा है कि शासन द्वारा जारी किये गये नियमों के तहत खरीदे गये इस गेहूं को सामान्य गेहूं के साथ नहीं मिलाया जायेगा। इस गेहूं का भंडारण और लेखा-जोखा पूरी तरह से अलग रखा जायेगा।

इनका कहना है -

विगत दिनों आंधी-तूफान की वजह से कुछ जगहों पर व्यवस्था बिगड़ गई थी। वहां छांव के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जो करवाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जिले भर के सभी केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बनाने के निर्देश दिये जा रहे है। आज तक 8965 किसानों से लगभग 48,772 एम.टी. (लगभग 4,84,724 क्विंटल) गेहूं की खरीदी की जा चुकी है।

- कृष्ण कुमार टेकाम, जिला खाद्य व आपूर्ति अधिकारी, बैतूल

प्रस्फुटन शक्ति संचय अभियान के अंतर्गत समितियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ

बैतूल। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित प्रस्फुटन शक्ति संचय अभियान अंतर्गत नर्मदापुरम एवं हरदा जिले की प्रस्फुटन समितियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत भारती परिसर बैतूल में सफलतापूर्वक प्रारम्भ हुआ। प्रशिक्षण में विकासखंड केसला, नर्मदापुरम, सिवनी मालवा एवं खिरकिया के प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक निदेशक म.प्र. जन अभियान परिषद डॉ. बकुल लॉड, वरिष्ठ समाजसेवी श्री अनिल अग्रवाल, श्री मुकेश त्यागी, श्री नरेन्द्र यादव तथा संभाग समन्वयक श्री कौशलेश प्रताप तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा श्रीमती प्रिया चौधरी द्वारा प्रस्तुत की गई।

मुख्य अतिथि डॉ. बकुल लॉड ने अपने उद्बोधन में प्रस्फुटन ग्रामों के विकास में सामुदायिक सहभागिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए जन अभियान परिषद की विभिन्न गतिविधियों एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्यों से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया।

प्रशिक्षण के तकनीकी सत्र संभाग समन्वयक कौशलेश प्रताप तिवारी, जिला समन्वयक प्रिया चौधरी एवं जिला समन्वयक नर्मदापुरम पवन सहगल द्वारा संचालित किए गए। सत्रों में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम के समापन सत्र जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर जी द्वारा प्रस्फुटन समिति के द्वारा आदर्श ग्राम बाचा का उदाहरण प्रस्तुत कर ग्राम विकास के लिए विभिन्न आयामों से अवगत कराया। सभी प्रशिक्षणार्थियों को श्री जितेंद्र तिवारी द्वारा जैविक कृषि प्रकल्प का भ्रमण कराया गया, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक एवं क्षेत्रीय अनुभव प्राप्त हुआ। इस अवसर पर हरदा जिला समन्वयक श्री संदीप गोहर, विकासखंड समन्वयक खिरकिया, विकासखंड समन्वयक केसला श्री विवेक मालवीय, नर्मदापुरम विकासखंड समन्वयक श्री नरेंद्र देशमुख, विकासखंड समन्वयक सिवनी मालवा श्री हरिदास दायमा एवं जिला कार्यालय से श्री दिनेश पंवार सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। ज्ञात हो दिनांक 6 मई से 13 मई तक नर्मदापुरम के 20 विकासखण्डो का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा हैं।

शराब दुकान हटाने जनसुनवाई में पहुंची महिलाएं

कांग्रेस नेत्री सीमा अतुलकर के नेतृत्व में किया प्रदर्शन

आमला। ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आज शराब दुकान हटाने की मांग लेकर खेड़लीबाजार कि महिलाओं ने कांग्रेस नेत्री सीमा अतुलकर ने नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन दिया। शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने जनपद चौराहे पर प्रदर्शन भी किया। अनुविभागीय अधिकारी शैलेंद्र बड़ोनिया को शिकायत करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि खेडलीबाजार ग्राम को बीचो बीच शराब दुकान संचालित होने से ग्रामीणों को परेशानी होती है।ग्राम में अस्पताल, सेवा सहकारी समिति ,शासकीय स्कूल एवं रहवासी क्षेत्र के बीच में शराब दुकान है। शराब दुकान पर प्रतिदिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है।

शराबियों के बीच गाली गलौच और मार-पीट की घटनाएं होती है। जिसके कारण ग्राम का माहौल बिगड़ता है। शराबियों के डर से महिलाओं को राशन दुकान से राशन लाने में परेशानी होती है। स्कूल की छात्राओं के साथ छेडछाड़ की घटना होने की आशंका बनी रहती है। शराब दुकान हटाने के लिए ग्राम पंचायत ने भी प्रस्ताव पारित किया था। लगातार आवेदन और निवेदन के उपरांत भी शराब दुकान अन्यत्र स्थानांतरित नहीं होने से महिला वर्ग भयभीत है। शिकायत में बताया कि 21 अप्रैल को कलेक्टर बैतूल और 11 मार्च को अनुविभागीय अधिकारी आमला को शिकायत की गई थी। 1 अप्रैल को खेड़ली बाजार की ग्राम सभा ने शराब दुकान का स्थान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया। लेकिन आज तक शराब दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया है।

शिकायतकर्ता महिलाओं के पति को शराब दुकान संचालक के लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी अप्रत्यक्ष रूप से दी जा रही है। शराब दुकान का स्थान परिवर्तन नही होने से ग्राम खेड़लीबाजार की जनता में अत्याधिक आकोश है यदि शीघ्र ही शराब दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया तो जनहित में चक्काजाम, भूख हडताल, आमरण अनशन करने के लिए जनता को मजबूर होना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार इस संबंध में प्रशासन ने आबकारी विभाग से उचित कार्यवाही करने को कहा है।

हेलमेट पहनें सुरक्षित रहें वसूले 56 हजार

सोहागपुर। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम एवं वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में चलाए गए। हेलमेट अभियान में सोहागपुर पुलिस ने दिनांक 26.4.26 से 10.5.26 तक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में सोहागपुर पुलिस ने दो पहिया वाहन चालकों को जागरूक किया गया। जिसमें हेलमेट पहने सुरक्षित रहे। इसी तारतम्य में बिना हेलमेट चालको के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान 179 प्रकरणों में 56 हजार 5 सौ रूपये का समन शुल्क भी वसूल किया गया। पुलिस ने बताया कि हेलमेट अभियान जागरूकता के तहत सोहागपुर थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर नागरिकों को समझाइस दी गई। वहीं ग्राम चारगांव सामूहिक विवाह में भी हेलमेट लगाने के लिए नवयुगल जोडों को प्रेरित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आए दिन बिना हेलमेट लगाने पर होने वाली दुर्घटनाओं को में कमी लाना है। पुलिस का मानना है कि पुलिस चालानी कार्यवाही ही इसका समाधान नहीं है। नागरिकों विशेषकर दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना है।

स्व. मनोज खंडेलवाल स्मृति विधायक ट्रॉफी 3 : रामगंज टाइगर विजेता, 72 फाइटर उपविजेता रही

सोहागपुर। स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल स्मृति विधायक ट्रॉफी 3 नाइट टेनिस बाल प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह क्षेत्रीय सांसद चौधरी दर्शनसिंह के मुख्य आतिथ्य एवं क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह के आतिथ्य तथा नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।इस अवसर पर अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। इसके उपरांत स्वर्गीय मनोज खंडेलवाल के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित की। फाइनल मुकाबला प्रारंभ होने के पूर्व राष्ट्रीय गान का आयोजन किया गया। बाद में आतिशबाज़ी जलाई गई। आयोजक पार्षद आशीष विश्वकर्मा मालवीय ने बताया नगर में पिछले दस दिनों से चल रही सोहागपुर प्रीमियर लीग नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का सोमवार को फाइनल महा मुकाबला हुआ। जिसमें आमंत्रित आठ टीमों ने भाग लिया था। सभी टीमों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया। अतः श्रेष्ठ प्रदर्शन करके रामगंज एवं 72 फाइटर फाइनल में पहुंची थी। आयोजक पार्षद आशीष विश्वकर्मा एवं यश खंडेलवाल ने सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ एवं माला से स्वागत किया। राष्ट्रीय गान के बाद में खिलाड़ियों ने अपने हाथो में विशाल तिरंगा थामे हुए थे। क्षेत्रीय सांसद एवं क्षेत्रीय विधायक ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया । रेफरियों ने टॉस कराया। जिसमें

रामगंज टाइगर ने टास जीता। प्रतियोगिता में- प्रत्येक चौके, छक्के, आउट होने पर डीजे, ढ़ोल बजने का नागरिकों ने आनंद लिया। फाइनल मुकाबला रामगंज टाइगर एवं 72 फाइटर्स के मध्य खेला गया। जिसमें 72 फाइटर्स ने पहले बल्लेबाजी निर्धारित 10 ओवर में 121 रन बनाए। रामगंज टाइगर्स ने धुआंधार बल्लेबाजी करते 9 ओवर में लक्ष्य हासिल कर खिताब अपने नाम कर लिया । इस अवसर पर अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते आयोजन की प्रशंसा की। वहीं क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने कहा कि सोहागपुर में प्रत्येक चार महीनों आयोजन होते रहेंगे। अतिथियों ने पत्रकारों पुलिस, नगर परिषद ,रेल्वे विभाग एवं टीम ऑनर्स को

सम्मानित किया। अतिथियों का स्वागत आयोजन कर्ता आशीष विश्वकर्मा एवं यश खंडेलवाल ने किया । विजेता टीम रामगंज टाइगर को 81 हजार एवं ट्रॉफी उपविजेता रही टीम 72 फाइटर्स को 41 हजार रुपए एवं ट्रॉफी प्रदान की गई । उक्त राशि विधायक विजयपा सिंह के द्वारा प्रदत्त की गई। अतिथियों ने मेन ऑफ द सीरीज सब्बीर शाह को खनूजा गैस एजेंसी कुंवर एवं एवं ट्रॉफी प्रदान की गई ।मेन ऑफ द मैच रामगंज टाइगर के जानू को प्रदान किया गया।फाइनल में अंपायरिंग शिवम दुबे, एवं रवि डे ने की। स्कोरिंग प्रवेश चौहान, विशाल मालवीय ने की। खेल का आंखों देखा हाल अंकित श्रोती, पवन रघुवंशी ने सुनाया। इसके अलावा अतिथियों ने कामेंट्री, स्कोरिंग ,अंपायरिंग ,बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेटकीपर ,बेस्ट फील्डर,बेस्ट दर्शक इमर्जिंन प्लेयर के पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम का गरिमामय संचालन पत्रकार संघ अध्यक्ष पवन सिंह चौहान ने किया।आयोजनकर्ता आशीष विश्वकर्मा ने आभार व्यक्त किया। पार्षद आशीष विश्वकर्मा के आग्रह क्षेत्रीय सांसद चौधरी दर्शनसिंह से रेल्वे पुल के नीचे से बने तिलक वार्ड रामप्रसाद वार्ड को जोड़ने वाले रोड की स्वीकृति किया। क्षेत्रीय सांसद चौधरी दर्शनसिंह ने शीघ्र स्वीकृति कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में दर्शक उपस्थित थे।

शॉर्ट न्यूज

नेट हाउस में इंग्लिश खीरा उत्पादन से किसान राजेन्द्र लोधी बने आत्मनिर्भर

सागर (निप्र)। सागर जिले के देवरी विकासखंड के ग्राम गौरझामर निवासी किसान राजेन्द्र लोधी ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर सफलता की नई मिसाल दी है। शासकीय परियोजना के अंतर्गत स्थापित नेट हाउस में उन्होंने पहली बार इंग्लिश खीरा की खेती कर उत्पादन प्राप्त किया है। किसान की इस उपलब्धि को जिले के 32वें सफल किसान मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। किसान राजेन्द्र लोधी ने नेट हाउस में इंग्लिश खीरा की फसल लगाई, जिससे उन्हें कम स्थान में अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। प्रथम फसल में उन्होंने लगभग 1350 किलो खीरा का उत्पादन किया। इस उत्पादन में कुल 5 हजार रुपए की लागत आई, जबकि बाजार में खीरा का औसत मूल्य 19 रुपए प्रति किलो प्राप्त हुआ। इससे किसान को कुल 25 हजार 650 रुपए की आय हुई तथा 20 हजार 650 रुपए की शुद्ध बचत प्राप्त हुई। किसान राजेन्द्र लोधी ने बताया कि नेट हाउस तकनीक का चमत्कारिक प्रदर्शन देखकर वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार इतनी कम जगह में बेहतर गुणवत्ता और अधिक मात्रा में खीरा उत्पादन देखकर उन्हें नई कृषि तकनीकों के प्रति विश्वास बढ़ा है। अब वे भविष्य में अन्य उन्नत फसलों का उत्पादन भी नेट हाउस के माध्यम से करने के लिए उत्साहित हैं।

अमानक बीज विक्रेताओं पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 10 लाइसेंस निरस्त

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में कृषि विभाग द्वारा बीज विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025-26 में अमानक एवं नियम विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 10 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त एवं निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने तथा कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न विकासखंडों में संचालित बीज विक्रेताओं की जांच के दौरान अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए गए। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसानों के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा अमानक बीज विक्रय करने वालों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। कार्रवाई के अंतर्गत लटेरी, कुरवाई, बासौदा, विदिशा एवं ग्यारसपुर विकासखंड के बीज विक्रेता शामिल हैं। इनमें कृषि सेवा केंद्र, एग्रीसीड्स कंपनी, किसान बीज भंडार एवं अन्य निजी बीज विक्रेता प्रतिष्ठानों के नाम सम्मिलित हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण बीज ही अधिकृत विक्रेताओं से खरीदना चाहिए। साथ ही बीज क्रय करते समय पक्का बिल लेना अनिवार्य है ताकि किसी प्रकार की शिकायत होने पर उचित कार्रवाई की जा सके। कृषि विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि यदि कोई विक्रेता बिना अनुमति या संदिग्ध गुणवत्ता के बीज विक्रय करता पाया जाए तो उसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें, जिससे समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

स्वास्थ्य केंद्रों में की गई 789 गर्भवती महिलाओं की जांच

सीहोर (निप्र)। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिये प्रत्येक माह की 09 एवं 25 तारीख को जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर देखभाल एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निशुल्क लाभ प्रदान किया जा रहा है, ताकि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अभियान के तहत 09 मई को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 789 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें 221 गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क पाई गईं। सीएमएचओ श्री सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क जाँच, दवाएं, एवं परामर्श दिया जा रहा है। अभियान के तहत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं विशेष देखभाल की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत प्रसव के समय जटिल अवस्था में उच्च चिकित्सा केन्द्रो में रेफर किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य जाँच के लिये निशुल्क पिक अप एवं ड्राप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण जागरूकता कार्यशाला आयोजित

सीहोर (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा बुधनी तहसील के ग्राम होलीपुरा में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य कृषकों एवं आमजन को जल संरक्षण के महत्व, वर्षा जल संचयन तथा सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के प्रति जागरूक करना था। कार्यशाला में किसानों को जल संरक्षण के व्यावहारिक उपायों, फसल जल प्रबंधन तथा उद्यानिकी फसलों में जल उपयोग दक्षता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कृषकों को खेत स्तर पर जल संरक्षण हेतु ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, मल्चिंग, फार्म पॉन्ड, एवं वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सरपंच श्री कमल सिंह ओझा सहित उद्यानिकी विभाग के अधिकारी और किसान उपस्थित थे।

सीएमएचओ ने उप स्वास्थ्य केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने 8 मई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीजादेही, उप स्वास्थ्य केन्द्र कुप्पा, बारजोरपुर, एवं हांडीपानी का औचक निरीक्षण किया।

जनगणना 2027:

वरिष्ठ अधिकारियों ने मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य का किया निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य जिले में निरंतर गति एवं गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशन तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट के मार्गदर्शन में सभी नगरीय एवं ग्रामीण चार्जों में फील्ड कार्य गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ संपादित किया जा रहा है।

जिले के कुल 2802 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में से लगभग 2100 एचएलबी में कार्य प्रगतिरत है, जबकि लगभग 700 एचएलबी का कार्य पूर्ण कर पोर्टल पर सफलतापूर्वक सिंक किया जा चुका है। जिले में अब तक लगभग 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार गौतम, जनगणना कार्य निदेशालय से नियुक्त जिला प्रभारी श्री भरत गौर, मास्टर ट्रेनर श्री विनोद अड़लक एवं तकनीकी टीम द्वारा विभिन्न नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर फील्ड कार्यों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। आज नगरीय चार्ज शाहपुर जिसमें 16 एचएलबी हैं, जिसमें से सुपरवाइजर सर्कल 02, कुल एचएलबी 5 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कमियों का सुधार करवाते हुए समय सीमा में कार्यपूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मकान नंबरिंग एवं नजरी नक्शों का किया जा रहा परीक्षण

निरीक्षण के दौरान प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा किए जा रहे मकान नंबरिंग, नजरी नक्शा निर्माण एवं एचएलओ एप में दर्ज प्रविष्टियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा स्थल स्थिति से मिलान कर जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मकान अथवा परिवार सर्वेक्षण से छूटने न पाए। डेटा की गुणवत्ता एवं सटीकता बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रविष्टि सावधानीपूर्वक दर्ज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

फील्ड स्तर पर तकनीकी सहयोग एवं शंका समाधान जारी

चार्ज स्तर पर गठित टीमों एवं फील्ड ट्रेनर्स द्वारा फील्ड में आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा रहा है। साथ ही प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को एचएलओ एप संचालन एवं डेटा प्रविष्टि संबंधी आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रगणकों को सही एवं तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कार्य में सहयोग प्रदान करें, जिससे विकास योजनाओं के लिए विश्वसनीय एवं सटीक आंकड़े प्राप्त हो सकें।

शिक्षा संबल योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी उपलब्ध कराना

शिक्षा संबल योजना के तहत निःशुल्क नीट कोचिंग प्रवेश परीक्षा सम्पन्न

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिला मुख्यालय पर आज एल.एन. माहेश्वरी परमार्थ न्यास एवं एलन करियर इंस्टीट्यूट, कोटा के संयुक्त तत्वावधान तथा एलेन इंदौर के समन्वय से संचालित 'शिक्षा संबल योजना' अंतर्गत निःशुल्क नीट-यूजी कोचिंग हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन रविवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, विदिशा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षा में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। शिक्षा संबल योजना का उद्देश्य सरकारी एवं हिंदी माध्यम के मेधावी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को एलन कोटा में निःशुल्क नीट-यूजी कोचिंग के साथ-साथ आवास एवं भोजन की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को बेहतर अवसर मिल सके।

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप विदिशा जिले को इस महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया। इससे जिले के विद्यार्थियों को अन्य शहरों में जाकर परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी तथा अभिभावकों और विद्यार्थियों को समय एवं आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली।

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर जिले के कुल 54 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुई। जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर मार्गदर्शन एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अवसरों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।

समीक्षा बैठक में की जल संवर्धन कार्यों की विस्तृत समीक्षा

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा शनिवार को जिला पंचायत सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में 'जल संचय जन भागीदारी 'एवं 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके अलावा सभी पंचायत को 31 मई के पूर्व अधिक से अधिक रीचार्ज फीट, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, शोखफीट सहित अन्य कार्य को पूर्ण किया जाकर प्रगति लाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संरक्षण, तालाबों का गहरीकरण, कुओं एवं बावड़ियों का पुनर्जीवन, जल स्रोतों की साफ-सफाई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरचनाओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने विकासखंडवार प्रगति की जानकारी लेते हुए अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण एवं पुनर्जीवन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आने वाले समय में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा एवं 'जल गंगा संवर्धन अभियान 'अंतर्गत पूर्ण किए गए सभी कार्यों की जानकारी समय पर पोर्टल पर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की वास्तविक प्रगति का सही आंकलन तभी संभव है, जब मैदानी स्तर पर पूर्ण कार्यों की ऑनलाइन एंट्री एवं जानकारी नियमित रूप से अद्यतन की जाए।

ई-चेक गेट के माध्यम से की जा रही खनिज परिवहन की निगरानी

खनिज परिवहन के लिए मानवरहित प्रणाली है ई-चेक गेट

सीहोर (निप्र)। प्रदेश में खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग द्वारा प्रदेश भर में 40 ई-चेक गेट प्रारंभ किये गये हैं। इनका संचालन 16 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील के गोपालपुर एवं बुधनी तहसील के गडरियानाला पर ई चेक गेट स्थापित किये गये हैं। ई-चेक गेट के माध्यम से खनिजों जिसमें गिट्टी, मुरम व रेत के परिवहन की निगरानी की जा रही है। इसमें गड़बड़ी होने पर चालानी कार्यवाही भी की जायेगी। जिला खनिज अधिकारी श्री धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि यह मानव रहित प्रणाली है जिससे खनिज परिवहन में लगे वाहनों की सतत् निगरानी हो सकेगी। इसके तहत परिवहन में लगे वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन टैग लगाना अनिवार्य होगा। यह फ्रंट विंडशील्ड पर लगाया जाएगा। ई-चेक गेट से गुजरते ही वाहन की पूरी जानकारी स्वतः ही सिस्टम में दर्ज हो जायेगी। इससे ओव्हरलोडिंग, नंबर प्लेट छिपाने या अन्य प्रकार की गड़बड़ी पर तत्काल कार्यवाही की जा सकेगी।ई-चेक गेट पर वैरिफोकल कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, आरएफआईडी रीडर जैसे आधुनिक उपकरण लगाये जायेंगे, जो वाहन संख्या, खनिज की मात्रा और वजन का स्वतः मिलान करेंगे। यदि ई-ट्रांजिट पास में दर्ज जानकारी और वास्तविक परिवहन में अंतर पाया गया तो संबंधित वाहन मालिक पर ऑनलाईन ही कार्यवाही की जाएगी। जिले में वर्तमान में दो ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं।

उल्लंघन करने पर पंजीयन होगा निरस्त

ई-चेक गेट जानकारी के आधार पर नियमों के उल्लंघन पर संबंधित वाहन का पंजीयन निरस्त या निलंबित किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त करने के निर्देश भी दिये जा सकेंगे। ई-चेक गेट से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर खनिज परिवहन में अनियमितता पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

संघर्ष से बबीता पंवार बनीं गांव के लिए प्रेरणा, आज हैं लखपति दीदी

आटा चक्की, सिलाई और ट्रैक्टर से आत्मनिर्भर बनीं बबीता पंवार

बैतूल (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है विकासखंड आमला के ग्राम तोरनवाडा की रहने वाली श्रीमती बबीता पंवार की है, जिन्होंने मेहनत, आत्मविश्वास और समूह की ताकत से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर आज 'लखपति दीदी 'के रूप में पहचान बनाई है। श्रीमती बबीता पंवार 'जय मां रेणुका आजीविका स्व-सहायता समूह 'से जुड़ी हुई हैं।

समूह से जुड़ने के बाद उन्हें मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सीआईएफ मद से 30 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस सहयोग से उन्होंने अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया और कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के प्रति उनका विश्वास बढ़ा। इसके बाद उन्होंने समूह के माध्यम से 1 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर गांव में आटा चक्की की शुरुआत की। साथ ही मिशन द्वारा दिए गए सिलाई प्रशिक्षण से उन्होंने सिलाई कार्य भी शुरू किया। आज बबीता दीदी अपने गांव में सफलतापूर्वक आटा चक्की और सिलाई कार्य संचालित कर रही हैं, जिससे उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त मिशन से जुडकर पोषण सखी सीआरपी के रूप में भी महिलाओं को उनके स्वास्थ्य पोषण से संबंधित जानकारी देकर स्वसहायता समूह से जुडी दीदीओं को जागरूक करने का भी कार्य कर रही है।

सीसीएल के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रूपये ऋण लेकर ट्रेक्टर खरीदा, जिससे उनके परिवार की आय में और वृद्धि होने लगी। आज वर्तमान में बबीता पंवार दीदी के परिवार की मासिक आय लगभग 15 से 20 हजार रूपये प्रतिमाह है और बबीता दीदी लखपति दीदी श्रेणी में आ चुकी है। अपनी लगन और मेहनत एवं पति की सहायता से उन्होने अपने पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम की है। श्रीमती पंवार की सफलता यह साबित करती है कि यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, अवसर और आत्मविश्वास मिले तो वे न केवल अपने परिवार, पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 650 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच

180 हाई रिस्क गर्भवतियों को विशेष उपचार व परामर्श प्रदान किया गया

विदिशा (निप्र)। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले में 09 मई को विशेष स्वास्थ्य जांच एवं उपचार शिविर आयोजित किए गए। कलेक्टर श्री अंशुल के निर्देशन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न शासकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर लगभग 650 गर्भवती महिलाओं की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया गया।

कार्यक्रम में 180 चिन्हित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विशेष रूप से जांच कर उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया गया। हाई रिस्क गर्भवतियों को एफसीएम एवं आयरन सुक्रोस लगाए गए, ताकि गर्भावस्था के दौरान एनीमिया एवं अन्य जटिलताओं को नियंत्रित किया जा सके। सीएमएचओ डॉ रामहित कुमार ने बताया कि अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच तथा सुरक्षित प्रसव संबंधी आवश्यक जानकारी एवं परामर्श भी दिया गया। साथ ही गर्भावस्था के दौरान सावधानियों और संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिले की प्रत्येक गर्भवती महिला को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और हाई रिस्क मामलों की निरंतर निगरानी कर सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके।

मध्यप्रदेश बन रहा देश का वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन हब

वाइल्डलाइफ संरक्षण, इको-टूरिज्म और रोजगार का उभरता केंद्र

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में ग्लोबल पहचान बनाई है। राज्य सरकार ने संरक्षण को केवल पर्यावरणीय दायित्व तक सीमित न रखते हुए उसे विकास, पर्यटन, स्थानीय रोजगार, सांस्कृतिक चेतना और सामुदायिक सहभागिता से जोड़कर व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इसी दूरगामी सोच से मध्यप्रदेश आज 'टाइगर स्टेट' के साथ ही देश के सबसे व्यापक और वैज्ञानिक वन्यजीव संरक्षण मॉडल के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विजन है कि प्रदेश के वन और नदियां केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। मध्यप्रदेश के वन देश की अनेक प्रमुख नदियों का मायका हैं। इस तरह ये वन कई राज्यों की जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसी सोच के साथ राज्य सरकार जलवायु अनुकूल, विज्ञान आधारित और समुदाय केंद्रित वन प्रबंधन मॉडल को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कार्यकाल में चीतों के साथ ही कई दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान दिया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से लाए गए जंगली भैंसों का पुनर्वास इस दिशा में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। यह प्रयास केवल एक प्रजाति को बसाने तक सीमित नहीं, बल्कि खो चुकी जैव-विविधता और पारिस्थितकी तंत्र को पुनर्जीवित करने का अभियान है।

इसी प्रकार चंबल, कूनो और नर्मदा क्षेत्र में घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी पहले से ही दुनिया में घड़ियालों की सबसे बड़ी शरणस्थली मानी जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा कूनो नदी में घड़ियाल और कछुओं को छोड़ना तथा ओंकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा नदी में मगरमच्छों का संवर्धन शुरू करना प्रदेश की जलीय जैव विविधता संरक्षण नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने जन्मदिवस पर वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, नौरादेही में संरक्षित प्रजाति के कछुओं को जल में विमुक्त कर प्रकृति और जैव विविधता के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। उनका मानना है कि वन्य और जलीय जीव पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन्यजीव संरक्षण में अब केवल रिजर्व बनाना पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि उनके बीच सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के अंतर्गत मध्यप्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच को जोड़ने वाली 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की मेगा टाइगर कॉरिडोर परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। एनएच-46 के इटारसी-बैतूल सेक्शन में अंडरपास और ओवरपास बनाए जा रहे हैं जिससे वन्यजीव सुरक्षित रूप से आवागमन कर सकें। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले हाईवे पर 'टेबल टॉप मार्किंग' जैसे रेड ब्लॉक बनाकर वाहनों की गति नियंत्रित की जा रही है। रातापानी टाइगर रिजर्व में 12 किलोमीटर लंबा साउंडप्रूफ कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिसमें वन्यजीवों के लिए सात अंडरपास बनाए गए हैं। यह मॉडल आधुनिक विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयास केवल वन संरक्षण तक सीमित नहीं है उनका फोकस वन आश्रित समुदायों को वन संरक्षण की प्रक्रिया का साझेदार बनाने पर भी है। सरकार की नीति है कि जब स्थानीय समुदायों को वनों से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, तब वे सबसे प्रभावी संरक्षक बनेंगे। इसी दृष्टि से 'विजनञ्च2047 ङ्क री-इमेजिनिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेस फॉर द क्लाइमेट रेसिलियंट फ्यूचर' दस्तावेज जारी किया गया।

गिद्ध संरक्षण में देश का नेतृत्व

मध्यप्रदेश गिद्ध संरक्षण में देश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंचे गिद्धों की संख्या राज्य में अब 14 हजार से अधिक हो चुकी है, जो देश में सर्वाधिक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी और वन विहार नेशनल पार्क के सहयोग से भोपाल के केरवा क्षेत्र में घायल गिद्धों के लिए रेस्क्यू सेंटर संचालित किया जा रहा है।

कूनो बना वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन का ग्लोबल प्रयोगशाला

श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क आज विश्व स्तर पर वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुए 'प्रोजेक्ट चीता' को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बोत्सवाना से लाई गई मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाया। वर्तमान में कूनो में चीतों की संख्या 57 तक पहुंच चुकी है। एक शताब्दी पूर्व लुप्त हो चुके चीतों की देश में सफल वापसी ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन और राजनीतिक प्रतिबद्धता के बल पर विलुप्त प्रजातियों का पुनर्वास संभव है। मध्यप्रदेश में चीतों साथ ही लुप्त हो चुकी 'जंगली भैंस' प्रजाति को भी कान्हा की घास-भूमि में आबाद किया जा रहा है। राज्य सरकार अब कूनो को 'ग्लोबल ब्रीडिंग सेंटर' के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। साथ ही गांधी सागर अभयारण्य को चीतों का दूसरा और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, नौरादेही को तीसरा बड़ा चीता लैंडस्केप बनाया जा रहा है। नौरादेही में चीतों के पुनर्वास के लिये सॉफ्ट रिलीज बोमा के निर्माण से परियोजना के अगले चरण का शुभारंभ हो चुका है।

नए टाइगर रिजर्व और अभयारण्य से बढ़ा संरक्षण क्षेत्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नेतृत्व में राज्य सरकार ने वन क्षेत्रों के विस्तार और जैव- विविधता संपन्न क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दिसंबर-2024 में रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के दर्जे के साथ वन एवं वन्य जीव संरक्षणको नया आयाम मिला। यह निर्णय वर्ष 2008 में अनुमति मिलने के बावजूद अब तक लंबित रहा था, इसलिए इसे ऐतिहासिक माना गया। इस टाइगर रिजर्व का नाम विश्वप्रसिद्ध पुरातत्वविद् पं. विष्णुदेव श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखा गया।

मार्च-2025 में शिवपुरी स्थित माधव टाइगर रिजर्व को प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहां मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए 13 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार भी बनाई गई है। इसी क्रम में अप्रैल 2025 में सागर जिले के 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'डॉ. भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य' घोषित किया गया। साथ ही ओंकारेश्वर और जहानगढ़ को नए वन्यजीव अभयारण्य के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगस्त 2025 में ताप्ती क्षेत्र को मध्यप्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया, यहाँ टाइगर, तेंदुआ, बायसन और जंगली कुत्तों जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं।

हाथी संरक्षण में वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण

राज्य सरकार ने हाथियों के संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए 47 करोड़ रुपये से अधिक की व्यापक योजना को मंजूरी दी है। राज्य स्तरीय 'हाथी टास्क फोर्स' का गठन, 'हाथी मित्र' योजना, रेडियो टैगिंग और सोलर फेंसिंग जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मानव-हाथी संघर्ष में जनहानि होने पर मुआवजा राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। साथ ही कर्नाटक, केरल और असम जैसे राज्यों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाकर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

रिटायरमेंट की राशि के लिए बाबू को चाहिए थी ढाई लाख की रिश्वत

1,00,000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त ने दबोचा

टीकमगढ़ (नप्र)। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शासकीय पीजी कॉलेज की तालकोठी शाखा में पदस्थ बाबू नितिन मिश्रा को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। कॉलेज परिसर में दिनभर इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा। वहीं, कर्मचारी और छात्र भी इस कार्रवाई को लेकर हैरान नजर आए।

रिटायरमेंट की राशि के लिए रिश्वत की मांग

जानकारी के अनुसार, कारी निवासी देवेंद्र वाल्मीकि ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की थी कि उनके पिता हरिकिशन वाल्मीकि शासकीय पीजी कॉलेज से स्वीपर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी लंबित रिटायरमेंट राशि और अन्य भुगतान निकालने के लिए कॉलेज की तालकोठी शाखा में पदस्थ बाबू नितिन मिश्रा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी बाबू ने पूरा काम कराने के बदले 2 लाख 50 हजार रुपए की मांग की थी।

लोकायुक्त ने बिछाया जाल

इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की तैयारी की। तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता को आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही बाबू नितिन मिश्रा ने शिकायतकर्ता से एक लाख रुपए की रिश्वत ली, पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए।

आरोपी से पूछताछ जारी

लोकायुक्त अधिकारियों द्वारा मौके पर दस्तावेजी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और यह भी पता लगाया जाएगा कि इस प्रकरण में कोई अन्य व्यक्ति शामिल है।

पहले ही आरोपी ने लिए थे 50000 रुपए

बताया गया है कि आरोपी पहले ही शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपए ले चुका था। इसके बाद वह लगातार बाकी रकम देने का दबाव बना रहा था। एक लाख रुपए की अतिरिक्त राशि तत्काल देने की मांग कर रहा था। परेशान होकर देवेंद्र वाल्मीकि ने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।